राष्ट्रपति ने माई भारत – राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 280 | रायपुर | मंगलवार 07 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

सीएम साय ने राजनाथ सिंह से दिल्ली में की भेंट :

नौसेना के नए पोतों का नामकरण होगा छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर

संवाददाता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाक़ात की। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास, पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन एवं नौसैनिक पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि बिलासपुर में रक्षा मंत्रालय की भूमि है। इस भूमि को उन्होंने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां रक्षा क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्य भी आरंभ करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ में सेना में भर्ती होने के प्रति युवाओं में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में अनुशासन, शारीरिक क्षमता और देशभक्ति की भावना है। इस आधार पर उन्होंने रक्षा मंत्री से आग्रह किया कि पूरे प्रदेश में विशेष सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाए, जिससे युवाओं को अपने ही प्रदेश में देश सेवा का अवसर मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली परंपराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नदियाँ – इंद्रावती, महानदी – केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि प्रदेश की आत्मा हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा मंत्रालय जब भी नए नौसैनिक पोतों या जहाजों को लॉन्च करे, तो उनमें से कुछ का नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और क्षेत्रों के नाम पर रखा जाए, जैसे INS इंद्रावती, INS महानदी या INS बस्तर। यह न केवल प्रतीकात्मक रूप से सुंदर होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को प्रोत्साहन देने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ÷आत्मनिर्भर भारत÷ के विज़न के अनुरूप है और इससे छत्तीसगढ़ में उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और निजी निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

बिहार में आचार संहिता लागू : बिहार चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे बोले चुनाव आयुक्त

बिहार का चुनाव 6 व 11 नवम्बर को होंगे मतदान,14 को आयेगा नतीजा

एजेंसी

नई दिल्ली/पटना. भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी.

कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस महायुद्ध को सिर्फ दो चरणों में संपन्न करने का फैसला लिया गया है, जो राज्य के इतिहास में पहली बार होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं वोटों की गिनती यानि मतगणना 14 नवंबर को होगी. पहले चरण में यानि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होंगे, वहीं दूसरे चरण यानि 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में इस बार एसआईआर की प्रक्रिया की गयी और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गयी. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव न सिर्फ बिहार के मतदाताओं के लिए सुगम होंगे बल्कि शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शी ढंग से मतदान कराएंगे. इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण सुझाव लिए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. इसमें 203 सामान्य सीटें हैं, 2 एसटी (ST) और 38 एससी (SC) सीटें हैं.

बिहार में 7.43 करोड़ वोटर्स हैं

बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7.43 करोड़ हैं. बिहार के फ र्स्ट टाइम वोटर्स 14 लाख हैं. इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर बूथ पर 1200 से अधिक मतदाताओं को नहीं रखने का निर्णय लिया है. ऐसे में इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगी. हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्ञानेश कुमार कहा- बिहार चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे. इस बार बिहार चुनाव मतदाताओं के लिए सरल, सुगम होंगे, पूरी लॉबी मतदाताओं की मदद के लिए खड़ी रहेगी, बिहार चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे, इस बार का बिहार चुनाव सबसे अच्छे चुनावों में शामिल होगा.

बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी : अमित शाह

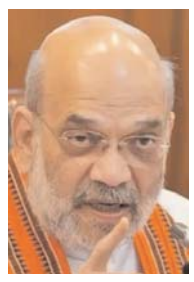

एजेंसी बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ÷चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए समस्त बिहारवासियों को बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने बिहार को जंगलराज से निकालकर विकास और सुशासन की नई दिशा दी है। आज बिहार, गरीब कल्याण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी।÷ बिहार चुनाव के ऐलान होते ही आपको बता दें कि नीतिश कुमार के साथ भाजपा का गठबंधन है और इस बार भी दोनों ही मिलकर चुनाव में लड़ रही है वहीं विपक्ष में तेजस्वी को चेहरा लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है। लालू परिवार में भी फूट पड़ चुकी है तेजप्रताप पहले ही अपनी पार्टी बना चुके हैं।

दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए SC का रुख करेगी दिल्ली सरकार

एजेंसी। काहिरा , संवाददाता।

एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिवाली के त्योहार के दौरान ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखित में अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेगी कि त्योहार के दौरान प्रमाणित ग्रीन पटाखों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जाए।

सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सभी ग्रीन पटाखे अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हों, जिन्हें सक्षम और संबंधित विभागों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। साथ ही, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर प्रभावी रोक और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया है कि इस संबंध में जारी किसी भी निर्देश को लागू करने के लिए वह पूर्ण सहयोग देगी।

SC से ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित पटाखा विनिर्माताओं को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, यह अनुमति एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ दी गई है, इन पटाखों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में बिना मंजूरी के नहीं की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले पर नए सिरे से विचार करे।

7 राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान

एजेंसी। बिहार चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग ने सात राज्यों में आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है. जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें राजस्थान की अंटा, जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल हैं. इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे. जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

भाजपा की ओर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं बिहार चुनाव

विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई मुलाकात

पटना: एजेंसी। बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मैथिली दरभंगा की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। विनोद तावड़े ने एक्स हैंडल पर 5 अक्टूबर को पोस्ट कर कहा था, ÷वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं!÷

विश्व

भारत का इस रूट पर चलेगी यह रेलगाड़ी

जल्द दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पहला हाइड्रोजन प्लांट तैयार

जींद , एजेंसी ।

हरियाणा के जींद से देश में स्वच्छ ऊर्जा के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट लगभग तैयार है और अगले 10-15 दिनों में इसका काम पूरी तरह पूरा हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय सहित कुछ विभागों से अंतिम स्वीकृति (एनओसी) मिलना बाकी है, जो जल्द मिलने की उम्मीद है।

प्लांट की जांच के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम में मिली कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल प्लांट में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन शुरू हो गया है और इसकी टेस्टिंग जारी है। यह प्लांट प्रतिदिन 430 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिस पर करीब 70 करोड़ रुपये की लागत आई है।

इस पायलट परियोजना के तहत एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ष्ठश्वरू) रैक को हाइड्रोजन ईंधन में अपग्रेड किया जा रहा है। सबसे पहले जींद-गोहाना-सोनीपत रेल मार्ग (करीब 89 किमी) पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन की गति 110 से 140 किमी प्रति घंटे तक होगी और इसमें एक बार में 2638 यात्री यात्रा कर सकेंगे। हाइड्रोजन की आपूर्ति इसी जींद प्लांट से की जाएगी। प्लांट में तीन हजार किलोग्राम भंडारण क्षमता वाला ईंधन स्टेशन, कंप्रेसर और तेज रिफ्यूलिंग के लिए प्री-कूलर इंटीग्रेशन वाले दो डिस्पेंसर लगाए गए हैं। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होगी, जो पारंपरिक डीजल ट्रेनों का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प साबित होगी। ट्रेन का इंजन धुएं की बजाय पानी और भाप छोड़ेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन शून्य रहेगा और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। भारत की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जा रही है।

दुश्मन की पनडुब्बियों की अब खैर नहीं, भारतीय नौसेना को मिलेगा 'साइलेंट किलर

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आईएनएस एंड्रोथ के कमीशन से नौसेना की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं में उल्लेखनीय मजबूती आएगी। विशेष रूप से तटीय या उथले जलक्षेत्रों में पनडुब्बी खतरों से निपटने की दिशा में यह पोत काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में नौसेना में शामिल हुए अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, निलगिरी और अब आईएनएस एंड्रोथ जैसे युद्धपोत भारतीय नौसेना के संतुलित और व्यापक विकास के प्रतीक हैं। ये सभी पोत भारत की 'आत्मनिर्भरता' की भावना को मूर्त रूप देते हैं।

एजेंसी।

नई दिल्ली भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी निर्माण कार्यक्रम के तहत आईएनएस 'एंड्रोथ' को कमीशन करने जा रही है। यह भारतीय नौसेना का दूसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे सोमवार को नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में एक भव्य समारोह में नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्वी नौसेना कमान के कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर उपस्थित रहेंगे। आईएनएस एंड्रोथ का कमीशन होना भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता में वृद्धि और स्वदेशीकरण के प्रति उसकी सतत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

हाल के महीनों में नौसेना के बेड़े में कई अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल हुए हैं। नौसेना के बेड़े में इस मजबूती से भारत की समुद्री शक्ति और तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

आईएनएस एंड्रोथ, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित है। यह भारत की बढ़ती समुद्री आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस युद्धपोत में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह पोत भारतीय नौसेना की उस सोच को मजबूत करता है, जो स्वदेशी तकनीक, नवाचार और घरेलू उद्योगों के सहयोग से उन्नत सैन्य क्षमताओं के विकास पर केंद्रित है।

नौसेना के इन जहाजों में डिजाइन, निर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता का अधिकांश हिस्सा भारतीय शिपयार्डों और उद्योगों से आता है। आईएनएस एंड्रोथ का कमीशन भारतीय नौसेना के उस विजन को भी साकार करता है, जो भारत को एक आत्मनिर्भर, सक्षम और आधुनिक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

कनाडा में तीन जगहों पर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी; सोशल मीडिया पर वीडियो जारी

टोरंटो/नई दिल्ली एजेंसी ।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी का दावा किया है। कनाडा में रविवार देर रात तीन अलग-अलग जगहों पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ली है। गैंग की ओर से किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि 2 नंबर के धंधे यानी अवैध कारोबार करने वालों से वसूली की जाती है, मेहनत करने वालों से नहीं। गैंग की ओर से पुर्तगाल में रहने वाले फतेह पुर्तगाल ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। उसने सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक शूटर अत्याधुनिक हथियार से गोलियां चलाता नजर आ रहा है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कनाडाई पुलिस ने सभी घटनास्थलों को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, पुलिस इसे संगठित अपराध से जुड़ी बड़ी साजिश के रूप में देख रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से ही गैंग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। खुद को 'फतेह पुर्तगाल' बताने वाले व्यक्ति ने पोस्ट में जिन तीन स्थानों का जिक्र किया है, वे हैं – Theshi Enterprise (1254, 110 Ave), House No. 2817 (144 St) और 13049, 76 Ave Unit No.104। दावा किया गया है कि ये सभी स्थान 'नवी तेसी' नामक व्यक्ति के स्वामित्व में हैं, जिसने कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर कलाकारों से अवैध वसूली की थी।

छत्तीसगढ़ की धरती सदा से रही है साहित्य और संस्कृति की धरा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर हुआ राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन

रायपुर। प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर हुआ राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजनछत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से विगत रात्रि आयोजित राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि को नमन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती सदा से साहित्य और संस्कृति की धरा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि महाकवि कालिदास ने इसी धरती पर मेघदूत जैसे अमर काव्य की रचना की, वहीं गजानन माधव मुक्तिबोध और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे यशस्वी साहित्यकारों ने इसी मिट्टी से अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया।प्रभु श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की पावन भूमि पर हुआ राज्य स्तरीय युवा कवि सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का यह अभिनव प्रयास प्रदेश की कला, साहित्य और रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन देने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा साहित्यकारों, रचनाकारों और कलाकारों को निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित तीनों विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस मंच के माध्यम से युवा कवियों को देश के ख्यातिलब्ध कवियों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे उनके रचनात्मक विकास को नई दिशा मिलेगी।छत्तीसगढ़ की संस्कृति गीत, नृत्य और भावनाओं का जीवंत संगम है : उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह सम्मेलन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा कवियों के लिए सीखने और सृजन की प्रेरणा का अवसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आरंभ से ही समृद्ध रही है – यहाँ मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक हर अवसर पर गीत गाए जाते हैं।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब खेतों में बुआई का समय आता है, तो पूरे वातावरण में ददरिया की मधुर ध्वनि गूंजती है। यहाँ विविध वाद्य, गीत, नृत्य और लोककलाओं की अनूठी परंपरा रही है। श्री साव ने कहा कि यह प्रदेश संतों, महात्माओं और कवियों की कर्मभूमि रहा है, जहाँ से समाज को सदैव नई दिशा मिली है। उन्होंने प्रदेशभर से आए युवा कवियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया। सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवि श्री शशिकांत यादव, श्री दिनेश बावरा, श्री नीलोत्पल मृणाल, सुश्री कविता तिवारी और सुश्री मनु वैशाली ने अपनी ओजपूर्ण एवं भावनात्मक कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

बस्तर अंचल के गांव-गांव के विकास कार्यों से आ रहा सकारात्मक बदलाव

सालेमेटा में 38.64 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि हमारी सरकार बस्तर अंचल के गांव-गांव के विकास के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य कर रही है। वे आज आज बस्तर जिले के सालेमेटा में 38.64 लाख रुपये की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। बस्तर तेजी से विकास की राह पर है और यह गति आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि सभी काम ईमानदारी से पूरे हों।

मछली पालन आय का उत्तम साधन, लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा रोजगार

समूह की महिलाएं 2 लाख 50 हजार रूपए की आमदनी कर रही अर्जित

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु खेती किसानी के साथ-साथ अन्य रोजगार से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा शासकीय तालाब को पट्टे पर देकर मछली पालन कार्य हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीच के साथ ही विभागीय योजना अंतर्गत निःशुल्क जाल और आईस बॉक्स भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिला के मनोरा विकासखण्ड में श्री गणेश महिला स्व सहायता समूह के द्वारा मनोरा के बथानडीपा शासकीय तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। समूह की अध्यक्ष गुड़िया साहू ने बताया कि गणेश महिला स्व सहायता समूह की 11 महिलाओं द्वारा मनोरा में शासकीय तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पान का कार्य किया जा रहा है। तालाब 0.801 हेक्टर में निर्माण किया गया है। उक्त तालाब में मछली पालन के लिए विभागीय योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज उपलब्ध कराया गया है। साथ ही योजना अंतर्गत निःशुल्क जाल एवं आईस बॉक्स भी दिया गया है। मछली पालन से समूह की महिलाओं ने 2 लाख 50 हजार रुपए की आय अर्जित किया है। समूह की सदस्यों ने बताया कि पहले से ही मछली पकड़ाने पालन विभाग द्वारा वे लाभान्वित हो चुके हैं। मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत जिले में 4 रूटों पर 5 अक्टूबर से बसों का संचालन होगा प्रारंभ

जशपुर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत अब जशपुर जिले में भी बसों का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। आज बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी कड़ी में जिले में 4 रूटों पर बस का संचालन किया जाएगा। कल 05 अक्टूबर निर्धारित समय पर बसें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत जिले में दुलदुला से अबिरा, पत्थलगांव से बुलडेगा, कैलाशगुफा से बगीचा और सन्ना से चम्पा रूट पर बस का संचालन किया जाएगा। इससे जिले के ग्रामीण अंचलों को बेहतर यातायात सुविधा प्राप्त होगी और आमजन को आवाजाही में बड़ी सहूलियत मिलेगी। आज रणजीता स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव,जनपद पंचायत दुलदुला अध्यक्ष राजकुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा एवं प्रशांत कुशवाहा, सीईओ जनपद पंचायत लोकहित भगत,बस संघ अध्यक्ष केदार मिश्रा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

गंगरेल के गेट खोलने से पानी में डूबी 900 एकड़ की फसल, किसानों ने किया चक्काजाम

पानी में बह गई सालभर की मेहनत, परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल

धमतरी।। प्रदेश में लगातार बारिश से गंगरेल बांध लबालब हो गया है। गंगरेल के 8 गेट खोलकर अचानक छोड़े गए पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। घुमा, पटेवा, ढुलना, कठोली सहित अन्य गांवों की लगभग 900 एकड़ धान की फसल पूरी तरह डूब गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फसल डुबने से आक्रोशित किसानों ने चक्काजाम कर सरकार और प्रशासन के खिलाफजमकर नारेबाजी की।

किसानों ने नवापारा कुरूद मुख्य मार्ग पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। चक्काजाम के चलते दोनों तरफ लगभग एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों ने इस दौरान आश्वासन नहीं, मुआवजा चाहिए, फसल का नुकसान सरकार भरे, किसानों का हक दिलाओ के नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुरूद और नवापारा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था संभाली और किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें ठोस कार्यवाही और समयबद्ध मुआवजा चाहिए। किसानों ने कहा कि हमारी सालभर की मेहनत पानी में बह गई, अब परिवार का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। 10 साल से सिर्फ भरोसा मिलता आ रहा है, इस बार बिना मुआवजा लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे। घंटों चले आंदोलन के बाद रायपुर और धमतरी जिले के किसानों के प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म किया।

25वीं राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रायगढ़ में हुआ रंगारंग शुभारंभ

रायपुर। रायगढ़ स्टेडियम में आज खेल भावना, अनुशासन और एकता के संदेश के साथ 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की आराधना कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया।इस राज्य स्तरीय आयोजन में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग से चयनित 632 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, खो-खो और क्रिकेट शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

सांसद श्री सिंह ने कहा कि खेल केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और प्रेरणा पाने का माध्यम हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वस्थ और सक्रिय युवा ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का अवसर दिया जाएगा। नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और एकता का प्रतीक हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से निष्ठा और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह किया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.वी. राव ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु सभी विभागों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। उद्घाटन समारोह में आकर्षक मार्चपास्ट और लोकनृत्य की प्रस्तुतियाँ हुईं।

पहले दिन के मुकाबलों में सॉफ्टबॉल बालक वर्ग में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर विजेता रहे। क्रिकेट बालिका वर्ग में रायपुर ने दुर्ग को 117 रनों से, जबकि सरगुजा ने बस्तर को 82 रनों से हराया। वॉलीबॉल वर्ग में बिलासपुर और बस्तर की टीमों ने जीत दर्ज की। यह प्रतियोगिता 8 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके लिए खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है।

मार्च 26 तक छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा लाल आतंक : अमित शाह

नक्सलवाद की वजह से नहीं पहुंचा बस्तर तक विकास

जगदलपुर, 05 अक्टूबर (आरएनएस)। बस्तर की सदियों से पहचान रहे बस्तर दशहरा में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को बस्तर के विकास में रोड़ा बताते हुए 31 मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने की हुंकार भरी. इसके साथ ही मुड़िया दरबार वैश्विक धरोहर बताते हुए इसके लोकतांत्रिक मूल्य को, पूरे देश के लिए जानकारी का विषय बताया. जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद जनसमुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 दिन के बस्तर दशहरा न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप से सबसे महत्वपूर्ण मेला है. आज सुबह दंतेश्वरी माई के दर्शन के दौरान प्रार्थना की है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों सालों तक भ्रम फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है. मैं बताने आया हूं कि पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा, इसका मूल कारण नक्सलवाद है. आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, पांच लाख तक स्वास्थ्य बीमा, पांच किलो मुफ्त चावल देने के साथ आपके चावल को 3100 रुपए से खरीदने की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें बस्तर पिछड़ गया है. मार्च 2026 के बाद नहीं रोक पाएंगे विकास अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे. काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है. मगर मुझे पूरा भरोसा 2026 मार्च से पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा. गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वे आप ही के गांव से हैं. उनको समझाइए कि मुख्य धारा में आएं. छत्तीसगढ़ शासन ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है. एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं।

बस्तर दशहरा : 'कुटुंब जात्रा' रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई

बस्तर दशहरा : 'कुटुंब जात्रा' रस्म के साथ हुई देवी-देवताओं का ससम्मान विदाई

रायपुर। अपनी अनूठी परंपराओं और रस्मों के लिए विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म, 'कुटुंब जात्रा', रविवार को स्थानीय महात्मा गांधी स्कूल परिसर के गुड़ी में संपन्न हुई। इस रस्म के तहत पूरे बस्तर संभाग एवं पड़ोसी राज्य ओडिशा व महाराष्ट्र के समीपवर्ती गांव से पर्व में शामिल हुए हजारों देवी-देवताओं के छत्र और डोली को बस्तर राजपरिवार के सदस्य श्री कमलचंद भंजदेव ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर ससम्मान विदा किया। यह रस्म 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व की समाप्ति की ओर इशारा करती है।

600 साल से अधिक पुरानी परंपरा

बस्तर दशहरा की सबसे खास बात यह है कि केवल इसी पर्व में इतनी बड़ी संख्या में एक-एक गांव के देवी-देवताओं के छत्र और डोली शामिल होते हैं। रियासत काल से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है, जिसमें राजा-महाराजाओं की तरह राजपरिवार के सदस्य और दशहरा समिति गांव-गांव से आए देवी-देवताओं और उनके पुजारियों को ससम्मान विदा करते हैं।परंपरानुसार, दशहरा पर्व में शामिल होने आए संभाग के सभी ग्राम के देवी-देवताओं को श्रृरूसूमश् (दक्षिणा/भेंट) भी दी गई। राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव और दशहरा समिति ने देवी-देवताओं के छत्र और डोली लेकर पहुंचे पुजारियों को कपड़े, पैसे और मिठाइयां देकर उनकी ससम्मान विदाई की। शहर के गंगामुण्डा वार्ड में स्थित देवगुड़ी में श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना अनुसार देवी देवताओं को भेंट भी अर्पित किया। बस्तर राजपरिवार और दशहरा समिति की अगुवाई में संपन्न हुई इस कुटुंब जात्रा रस्म के साथ ही, 600 साल से अधिक पुरानी बस्तर दशहरा पर्व की परंपराएं विधि विधान से पूरी की गईं। इस दौरान पूरे परिसर में उपस्थित देवी-देवता का आपस में मेल मिलाप देखते ही बन रहा था। देवी देवताओं के लाठ, डोली के साथ झुमते सिरहा और विभिन्न क्षेत्रों के आंगादेव का खेल माहौल को आकर्षक एवं अचम्भित किया। इस अवसर पर स्थानीय एवं आस-पास के गांव से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी

ऑपरेशन साइबर शील्ड: रायपुर पुलिस ने किया करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश

रायपुर। रेंज पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के एक विशाल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रेंज पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में उड़ीसा, गुजरात, बिलासपुर और रायपुर के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

फर्जीवाड़े का तरीका और खुलासा

गिरफ्तार किए गए आरोपियों गजसिंह सुना (उड़ीसा), भिखु सचदेव (गुजरात), साहिल कौशिक (बिलासपुर), और हर्षित शर्मा (रायपुर) को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

साइबर क्राइम पोर्टल में दर्ज 'म्यूल बैंक अकाउंट' (किराए पर लिए गए बैंक खाते) की जांच के बाद यह खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 50 मोबाइल, 10 डेस्कटॉप, सिम कार्ड और अन्य उपकरण जब्त किए हैं।

मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ठगी

ठगी के लिए गिरोह ने जैसी फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स बनाई थीं। इन साइट्स पर वर-वधू की फर्जी तस्वीरें दिखाकर लोगों को झांसे में लिया जाता था। पुलिस ने रायपुर के गोल चौक डगनिया और कटोरा तालाब स्थित फर्जी कार्यालयों पर भी छापेमारी की।

चीनी कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग

पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि इन म्यूल अकाउंट्स का नियंत्रण एक चीनी नागरिक (क्क्य) के जरिए किया जाता था। ये खाते मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए जाते थे, और ट्रांजैक्शन की रकम के आधार पर आरोपियों को कमीशन मिलता था।

रेंज साइबर थाना इस मामले की व्यापक जांच कर रहा है। बैंकों से असामान्य ट्रांजैक्शन वाले अन्य अकाउंट्स की जानकारी भी पुलिस को मिल रही है, जिससे इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की उम्मीद है। सभी संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है।

एआईसीसी ने भूपेश को बिहार चुनाव में बनाया सीनियर ऑब्जर्वर

41 जिला पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्त

रायपुर। । बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को शनिवार को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीनों वरिष्ठ नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त करने को मंजूरी दी है।

कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी की इस यात्रा से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। कांग्रेस नेताओं के साथ महागठबंधन के नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। वोट अधिकार यात्रा में लोगों की भीड़ भी जुटी। अब कांग्रेस इस समर्थन को वोट में तब्दील करना चाहती है।

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी

वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के अलावा कांग्रेस ने 41 नेताओं को जिला चुनाव पर्यवेक्षक बनाया है। इनमें अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, अजय राय, सतेज बंटी पाटील और भक्त चरण दास जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी ने संगठन में संतुलन बनाने के लिए युवाओं को भी बड़ी भूमिका दी है। कांग्रेस ने श्रीनिवास बी.वी., तनुज पुनिया, विक्रांत भूरिया और अभिषेक दत्त जैसे कई युवा नेताओं को जिला चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपकर आने वाले चुनाव में युवाओं को जोड़ने का संदेश दिया है।

अगले महीने संभावित चुनाव

सूत्रों के मुताबिक अगले महीने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में चुनावी रणनीति मजबूत करने कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारना कोशिश शुरू कर दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि अनुभवी नेताओं और युवाओं का यह संयोजन बिहार की सियासत में संगठन को नई ऊर्जा देगा।

भूपेश बघेल कांग्रेस के एटीएम - सांसद पांडेय

रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय कोंग्रेश कमेटी द्वारा बिहार राज्य के ऑब्जर्वर बनाए जाने पर तंज कसते हुए अनेक आरोप लगाए। राजनादगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कहा की भूपेश बघेल को राहुल और प्रियंका गाँधी एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे है उन्हें उत्तराखंड ,पंजाब जैसे राजयो में कमान सौपी गई उन राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप को लेकर देशभर में मचा हड़कंप, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी

रायपुर। कोल्ड्रिफ कफ सिरप को लेकर देशभर में चिंता का माहौल है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में इस सिरप के सेवन से अब तक 12 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके चलते मध्यप्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं।

यह कफ सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की फार्मा कंपनी श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित की गई है। प्राथमिक जांच में इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा खतरनाक स्तर तक पाई गई है, जो शरीर के लिए अत्यधिक विषैली होती है और इससे गुर्दे फेल होने जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य में इस कंपनी की सिरप की कोई आपूर्ति नहीं की गई है। लेकिन एहतियातन इस सिरप को राज्य में भी प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी तरह की आशंका या भ्रम की स्थिति न बने। विभाग ने बताया कि बाजार में निगरानी बढ़ा दी गई है और संबंधित दवा की बिक्री रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दवा व्यवसायी अश्वनी विग ने जानकारी दी कि राज्य में न तो कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री हो रही है और न ही श्रीसन फार्मा का कोई गोदाम यहां मौजूद है। इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों में बच्चों की मौत की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सिरप की तस्वीरों के चलते लोगों में डर का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और यदि इस सिरप से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या प्रशासन को सूचित करें। राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सतर्कता बढ़ा दी है।

पूणे और मुबंई के तीन एजेंटों ने किया करोड़ों का जमीन घोटाला, रेरा ने खरीदी-बिक्री पर लगाई

राजधानी के डोमा गांव की 50 एकड़ सरकारी जमीन का मामला

रायपुर। । राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। यहां करीब 50 एकड़ सरकारी भूमि को पहले किसानों के नाम आवंटित किया गया और फिर योजनाबद्ध तरीके से इसे निजी कंपनियों और एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया गया। इस पूरे खेल की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, डोमा गांव (प.ह. नं. 84) की भूमि लंबे समय से राजस्व रिकॉर्ड में घास और चराई की जमीन के रूप में दर्ज थी। ऐसी भूमि किसी भी स्थिति में निजी स्वामित्व में नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद कुछ किसानों को इसका आवंटन कर दिया गया। बाद में इन किसानों से दो नामी कंपनियों स्वास्तिक प्रोजेक्ट्स और रूपी रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन खरीद ली। चौंकाने वाली बात यह रही कि अधिकारियों ने भी बिना किसी गहन जांच के यह ट्रांसफर मान्य कर दिया और करोड़ों की सरकारी जमीन निजी हाथों में पहुंच गई। इसके बाद यह भूमि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को

बेच दी गई, जिसने आगे प्लॉटिंग कर बिक्री की तैयारी शुरू कर दी।

बिना पंजीयन ही शुरू हुई बिक्री

रेरा (रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) के मुताबिक, इस परियोजना का पंजीयन तक नहीं कराया गया था। इसके बावजूद सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। शिकायत दर्ज होने पर रेरा ने जांच की और परियोजना की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। रेरा ने इस मामले में तीन एजेंटों शशिकांत झा (पुणे), दीक्षा राजौर (मुंबई) और प्रॉपर्टी क्लाउड्स रियल्टी स्पेसिफायर प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई) को नोटिस जारी किया है। इन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खर्रानाला स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए मिली प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। राज्य शासन ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड शंकरगढ़ में खर्रानाला स्टापडेम निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना की कुल स्वीकृत लागत 3.74 करोड़ रूपये (तीन करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में निस्तारी, भू-जल संवर्धन, पेयजल उपलब्धता तथा लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों द्वारा सिंचाई सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव को वित्त एवं योजना विभाग की समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा तत्पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि कार्य स्वीकृत राशि और समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाए तथा निविदा प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए। कार्य की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और शासकीय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह परियोजना क्षेत्र में जल संसाधन विकास, भू-जल संवर्धन और कृषकों की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

आरंग में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय

रायपुर । केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रायपुर जिले के आरंग में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अवसरों के विस्तार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय न केवल आरंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि आस-पास के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की नई चेतना जागृत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी अंचलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने, स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा का नया युग प्रारंभ हो रहा है।

नवा रायपुर में अवैध विकास पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई

रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध विकास और निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम टेमरी और डूमरतराई थोक मार्केट से लगे क्षेत्र में बिना अनुमति किए जा रहे भूमि विकास और सड़क निर्माण को आज संयुक्त टीम ने हटाया।यह कार्रवाई राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा की गई।प्राधिकरण को पहले प.ह. नं. 78 के रख. नं. 168, 167, 162, 165, 177 एवं अन्य भागों में अवैध विकास एवं निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के बाद संबंधित भू-स्वामी, विकासकर्ता और निर्माणकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

चांदी की झूठी लूट की कहानी रचने वाला कारोबारी गिरफ्तार

रायपुर। डिजिटल निगरानी के इस दौर में झूठी कहानियों से बच निकलना अब आसान नहीं रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है रायपुर में, जहां एक चांदी कारोबारी ने करोड़ों की लूट की फर्जी कहानी गढ़ दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो गया।

आरोपी राहुल गोयल, जो मूल रूप से अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, रायपुर में 'शिवा ट्रेडर्स' नाम से चांदी का कारोबार करता है। वह आगरा की एक कंपनी का अधिकृत सीएफए (कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट) है, और वहां से चांदी के आभूषण लाकर रायपुर के व्यापारियों को सप्लाई करता है। प्रति किलो 500 रुपये का कमीशन उसका मुख्य मुनाफा होता है।

राहुल ने पुलिस को बताया कि दिवाली के लिए वह करीब 200 किलो चांदी रायपुर लाया था। इसमें से 100 किलो वापस आगरा भेज दी गई, जबकि 14 किलो की बिक्री हो

चुकी थी। शेष 86 किलो चांदी का ऑर्डर बाकी था। शुक्रवार रात उसने दावा किया कि खाना खाने के बाद वह सो गया और रात करीब 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर दो नकाबपोश थे, जिन्होंने हथियार दिखाकर उसके घर में घुसकर चांदी लूट ली।

उसका कहना था कि विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला किया गया और उसे बेहोश कर दिया गया। होश में आने पर उसने खुद को बंधन से छुड़ाया और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि लुटेरे रस्सी के सहारे बालकनी से भागे और साथ में DVR (CCTV रिकॉर्डिंग सिस्टम) भी ले गए।

हालांकि, पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो कहानी में कई झोल नजर आए। CCTV, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और आस-पड़ोस की पूछताछ के आधार पर साफ हो गया कि कोई लूट हुई ही नहीं। जांच में पता चला कि राहुल जुए और सट्टे में भारी रकम गंवा चुका था। उसने नुकसान की भरपाई और उधार चुकाने से बचने के लिए यह नाटक रचा था।पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब उस पर झूठी FIR दर्ज करने, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि तकनीक के युग में अपराध छिपाना आसान नहीं है। झूठ और धोखे की कितनी भी परत चढ़ा ली जाए, सच सामने आ ही जाता है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों को डीआर देने के आदेश जारी करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब कर रही है

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विगत शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार से पेंशनरों और परिवार पेंशनरों हेतु एरियर सहित 5त्न प्रतिशत डीआर के आदेश तुरंत जारी करने की मांग की गई। बैठक में बिना एरियर के आदेश जारी करने पर इसके विरोध में पूरे प्रदेश में डीआर आदेश का होली जलाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेंशनरों को डीआर देने के आदेश जारी करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब कर पेंशनरों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जबकि राज्य में पेंशनरों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए बिना एरियर 2त्न प्रतिशत मंहगाई भत्ता के आदेश 25 अगस्त को बहुत पहले जारी कर चुकी है परंतु उसके बाद से अपनी बारी का पेंशनर इंतजार कर रहे है नवरात्रि और दशहरे के पहले मिलने की आस टूटने के बाद अब

दिवाली के पहले आदेश का भरोसा कर रहे है। जनवरी का 2त्न प्रतिशत अभी बकाया है और अब केंद्र सरकार ने जुलाई से 3त्न प्रतिशत वृद्धि कर दिया है। इस तरह अब राज्य को केंद्र के समान 5त्न प्रतिशत डीआर पेंशनरों को देना है मगर सरकार की चुप्पी से हैरानी हो रही है। बैठक में नवंबर माह में जन्म लिए आजीवन सदस्य क्रमशः आर के दीक्षित, भीमराव जाम्हले,मालिक राम वर्मा और आर के टंडन को पौधा भेंट कर पुष्पहार पहना कर उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर बैठक में पूरन सिंह पटेल, जेपी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह,लोचन पाण्डे, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, एम एन पाठक, बी एस दसमेर, अनिल पाठक, आर के साहू ,नरसिंग राम, शैलेन्द्र सिन्हा, नागेन्द्र सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। आज जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स की मुख्य समस्या केंद्रीय गृह विभाग के एक्ट मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके छत्तीसगढ़ प्रवास पर मिलना चाहता था। इसके लिए रायपुर और बस्तर दोनों जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया किंतु उन्होंने अनुमति नहीं दिया। जिसके वजह से उनसे न चर्चा हो सकी न ही उनको ज्ञापन देना संभव हुआ।पेंशनर्स महासंघ ने जिला प्रशासन के इस रवैए पर रोष जताया है।

प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने भाजपाइयों के साथ किया निर्माणाधीन अटल चौक का निरीक्षण

अटल जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान का स्मरण कराती रहेगी - रंजना साहू

जयंती के पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने अधिकारियों दिया गया है टारगेट - नरेंद्र रोहरा

रायपुर । शहर के बायपास मोड़ पर निर्माणाधीन अटल चौक का मंगलवार को प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रंजना साहू एवं नगर निगम सभापति द्वय नरेंद्र रोहरा एवं विजय मोटवानी ने भाजपाइयों के साथ निरीक्षण किया,यह चौक नगर के प्रवेश पर बनाया जा रहा है,जिसको लेकर भाजपा के डेलीगेशन ने निरीक्षण कर कार्य का जायजा लिया,इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा प्रदेश के निर्माता स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा छत्तीसगढ़ के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान का स्मरण कराती रहेगी,प्रदेश की की विष्णु देव साय सरकार द्वारा हर जिले हर ब्लॉक में अटल जी की प्रतिमा लगाने का फैसला उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए राष्ट्र हित में कार्यो को याद कराता रहेगा,धमतरी के प्रवेश पर अटल जी की यह प्रतिमा जल्द ही लोकार्पित होगी,नगर निगम सभापति नरेंद्र रोहरा ने कहा अटल जी की प्रतिमा का यह कार्य जल्द पूर्ण होगा और जानता को समर्पित होगा,उनकी जन्मजयंती से पूर्व इस कार्य को पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है,नगर निगम धमतरी पूरी तन्मयता से इस कार्य को पूर्ण करेगा ऐसा आश्वासन सभापति द्वय ने दिया।

संपादकीय

पाकिस्तान सावधान खुद सुधरो या टूटो

हमारी थल सेना और वायु सेना के प्रमुखों ने पाकिस्तान को सीधे, साफ शब्दों में चेतावनी दी। अगर आंतकवाद से तौबा नहीं की, अगर भारत की तरफटेढ़ी आंख से देखा तो पाकिस्तान का नामो-निशान मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने भारत-पाक सरहद पर तैनात जवानों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट पार्ट में तो सेना ने संयम बरता, लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान भूगोल से गायब हो जाएगा। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज के मिसाइलों और विमानों का सफल परीक्षण हो चुका है, पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है,अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा, तो अंजाम क्या होगा, ये पाकिस्तान की फौज अच्छी तरह जानती है।

मुंबई हमलों 26/11 पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान का अर्थ

अजय दीक्षित

2008 में 26 नवम्बर को मुंबई के ताज होटल और बंबई रेलवे स्टेशन, सहित 7 स्थानों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलें पर बोलते हुए तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की ।यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कंडोला राइस के दिल्ली में मुलाकात के बाद लिया जबकि वे पी चिदंबरम चाहते थे कि भारत को पाकिस्तान को सैन्य ताकत से जवाब देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इन हमलों में 200 से अधिक लोगों को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था जिसमें से एक आतंकी मोहम्मद कसाब को मुंबई पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था जिसे 2012 में फांसी दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज को हटाकर तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम को 26 नवंबर को गृह मंत्री बनाया था । सत्रह साल बाद पी चिदंबरम ने उस समय उक्त बात स्वीकार की है जब अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना पर सवाल उठा रहे हैं।यह भी पूछ रहे हैं कि युद्ध में भारत कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए ।

पी चिदंबरम ने अमेरिका के दबाव में तत्कालीन समय में मुंबई हमलों के बाद 2008 में कार्यवाही न करने की बात कह कर जैसे कांग्रेस की पोल खोली दी हो।

तत्कालीन हालातों पर गौर करें तो उस दिन मुंबई पुलिस के एक बड़े आइपीएस अधिकारी हेमंत करकरे, और कई छोटे बड़े पुलिस बल के लोग भी मारे गए थे और पकड़े गए कसाब ने ही उस समय मारे थे जब कसाब को जिंदा पकड़ ने की कोशिश हो रही थी। आतंकी मोहम्मद कसाब ने बताया था कि वह करांची के रास्ते समुद के माध्यम से 14 आतंकियों के साथ आया था और उसकी ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई थी और पाकिस्तान के सेना ने दी। तत्कालीन समय में इतने पुख्ता सबूत मौजूद थे लेकिन फिर भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर कोई सार्थक कारवाही नही की ।यह राज तब तक राज था जब तक कि पी चिदंबरम ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया।

कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में चीन युद्ध के दौरान भी बहुत ढुलमुल रवैया अपनाया था और सारा ठीकरा कृष्ण मेनन के सिर फोड़ दिया। यद्यपि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। अगर गंभीरता से पी चिदंबरम के कथन की विवेचना करे तो यह समय कांग्रेस की भीतरखाने ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की कहानी है।जो गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर से पी चिदंबरम तक पहुंची है।

राहुल गांधी आजकल राजनीतिक व्यवस्था से जैसे ऊब गए हो gen5 की बाते कर रहे हैं,चुनाव आयोग को निशाना बनाना चाहते हैं कैसे भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं चाहे वह रास्ता बांग्लादेश से नेपाल हो कर जाय।राहुल गांधी कांग्रेस के तीन चुनाव 2014,2019,2024, हारने से हतोत्साहित मुद्रा में हैं और राज्यों में भी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तमिलनाडु

में सरकार में है । झारखंड, तमिलनाडु,में जेएमएम,डीएमके के भरोसे है ।243 की राज्य सभा में अब मात्र 31 सांसद हैं। ऐसे माहौल में राहुल गांधी का जो हाल है वह अप्रत्याशित नहीं है। राज्यों मप्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, बिहार पश्चिमी बंगाल असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़,के कांग्रेस का नेतृत्व टूट रहा है और पी चिदंबरम भी उसी पीड़ा के परिणाम है। **यह निजी विचार है।**

मोटापे और कुपोषण से सीधे निपटना मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 रणनीति

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

2018 में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जीके दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत के पोषण परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में पोषण अभियान शुरू किया गया था। महिलाओं और बच्चों के पोषण एवं कल्याण पर केंद्रित यह मिशन, भारत की कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है।यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक विकासशील भारत के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता है- एक ऐसा भारत जो स्वस्थ, सशक्त और समावेशी हो।'विकसित भारतञ्च2047' की यात्रा में पोषण अभियान एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पित है- एक ऐसा भारत जहाँ हर बच्चा सुपोषित हो, हर माँ सशक्त हो, और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

जब एक बच्चा सही पोषण पाता है, अच्छीतरह सीखता है और मजबूतीसेबढ़ता है- तो हम केवल एक जीवन नहीं, बल्कि सम्पूर्णराष्ट्र की दिशा बदलते हैं। बच्चों को पर्याप्त पोषण, शिक्षा और सामुदायिक देखभाल प्रदान करके हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में निवेश कर रहे हैं- विकसित भारत के भावी नेतृत्व को आकार दे रहे हैं। एक स्वस्थ बच्चा केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की चिंगारी है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण2.0 के माध्यम से मंत्रालय बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों को बेहतर बनाने हेतु एक समन्वित तंत्र विकसित कर रहा है। इस अभियान का केंद्र है, देशभर में फैले 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का विशाल नेटवर्क, जो लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रहा है। यद्यपि इसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएँ और 23 लाख से अधिक किशोरियाँ शामिल हैं, लेकिन लाभार्थियों में से अधिकांश 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'एक समय पर एक भोजन' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए 8 करोड़ से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के ज़रिए, भविष्य को पोषित कर रहा है। इस प्रयास का मूल है- पूरक पोषण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और सभी लाभार्थियों को पौष्टिक टेक होम राशन प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआई) के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है। हम विविध आहार को अपनाते हुए स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे श्री अन्न- जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू आदि को बढ़ावादेकर- हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने, बढ़ने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिले।

जहाँ हमने बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्याओं सेनिपटने में प्रगति की है, वहीं अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण पोषण संकेतक- अधिक वजन और मोटापे की समस्या को भी दूर करने की दिशा में अग्रसर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बचपन में मोटापा बच्चों के वयस्क होने पर उनके लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिससे टाइप-2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे और अधिक वजन के मनोवैज्ञानिक परिणाम भी हो सकते हैं, जो स्कूल के प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, और बढ़ते भेदभाव और कलंक के कारण यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया बर्कले और मैकगिल के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को गर्भावस्था के दौरान गर्भ में रहते हुए भी, अपने पहले 1,000 दिनों के दौरान चीनी सेवन पर नियंत्रण लगाया गया, उनमें वयस्क होने पर टाइप 2 मधुमेह होने का जोखिम 35 प्रतिशत तक कम और उच्च रक्तचाप होने का जोखिम 20 प्रतिशत तक कम हो गया। यह दर्शाता है कि गर्भवती माँ का चीनी सेवन भी बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

इस समस्या के समाधान और पूरक पोषण की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरक पोषण की संरचना के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) की सिफारिशों के अनुरूप है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों के अनुसार, वयस्कों और बच्चों, दोनों के लिए चीनी का सेवन कुल दैनिक ऊर्जा सेवन के 10 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। WHO दैनिक ऊर्जा सेवन में अधिमुक्त शर्करा (free sugars)की मात्रा को और घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान ह्वह्व की 2024 के आहार दिशानिर्देशों के अनुसार, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई अतिरिक्त चीनी नहीं दी जानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं सहितसभी आयु व जेंडर समूहोंके लिए चीनी का सेवन 5 प्रतिशतसे कम होना चाहिए।

अधिमुक्त शर्करा बच्चों में दंत क्षय (cavities) और दांतों की सड़न- का एक प्रमुख कारण भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यहदंत क्षय(कैविटी)कोबढ़ाने में एक आवश्यकआहार कारक है। चीनी सेवन को सीमित करने से बच्चों में दांतों की सड़न और क्षय को कम किया जा सकता है।

हमारेमंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग सीमित किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर गुड़ या अन्य प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करें, और इसे कुल ऊर्जा सेवन के 5 प्रतिशत से कम तक सीमित रखें।हमने अनुरोध किया है कि पूरक पोषण में नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुबह के नाश्ते और स्वास्थ्यवर्धक आहार में मिठास वाले व्यंजनों की संख्या भी घटाने का आग्रह किया गया है।

हम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे ञ्च॥क्रव्यंजन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनमें अतिरिक्त नमक और चीनी न हो, जिससे लाभार्थी अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार स्वाद बदल सकें। सभी आयु समूहों में वसा, नमक और चीनी (॥स्नस्स्) की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी हतोत्साहित किया गया है। खाद्य गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि सामग्री को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 का पालन करना चाहिए और शिशु आहार खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण हेतु खाद्य) विनियम, 2020 का पालन करना चाहिए।अतिरिक्त चीनी को 'ना' कहकर, भारत मोटापे, उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी रोकथाम योग्य बीमारियों से मुक्त भविष्य के लिए 'हाँ' कह रहा है।

जहाँ पारंपरिक खाद्य पदार्थ बाज़ार में लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं मंत्रालय पहले से ही 'पुष्टाहार'- स्थानीय, मौसमी सामग्री और अनाज जैसे रागी, बाजरा, टुकड़ा गेहूँ, चनाऔर फोर्टिफाइड चावल से बने पौष्टिक प्रीमिक्सप्रदान कर रहा है। ये मिश्रण- स्वाद और पोषण दोनों में समृद्ध हैं, जिन्हें स्थानीय स्वादानुसार मीठे या नमकीन रूप में तैयार किया जा सकता है। पुष्टाहार, दुकानों से खरीदे जाने वाले मिश्रणों का एक स्वास्थ्यवर्धक और अधिक बहुमुखी विकल्प है, जो स्थानीय, मौसमी स्वाद और संपूर्ण पोषण प्रदान करता है।

जैसे-जैसे हम अपने नागरिकों को पर्याप्त कैलोरी प्रदान करके सुपोषित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों और महिलाओं को जो भोजन दिया जा रहा है,उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों, जो हमारे देश का भविष्य हैं, को जो भोजन प्रदान करते हैं, वह उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

हमारेमाननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अपने खान-पान की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपने भविष्य को अधिक मजबूत, स्वस्थ और रोग-मुक्त बना सकते हैं। इस अमृत काल में, हमारे बच्चों को पौष्टिक भोजन और पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए भोजन न केवल पर्याप्त होना चाहिए, बल्कि पौष्टिक भी होना चाहिए, जो उनके समग्र विकास और वृद्धि में योगदान दे।

यह निजी विचार है।

बिहार में शंकराचार्य का चुनावी शंखनाद 'गौ रक्षा' बनेगी सियासत का नया एजेंडा

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

बिहार की राजनीति में इस बार जातीय समीकरणों और विकास के वादों से अलग एक नया मुद्दा तेजी से उभरकर सामने आया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शिवहर से अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत करते हुए स्पष्ट ऐलान किया है कि वे राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। उनका कहना है कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता की रक्षा हो और यही इस चुनाव की असली कसौटी होगी। उनके इस एलान के बाद बिहार की चुनावी राजनीति में हलचल मच गई है और हर दल इस नए समीकरण को लेकर गणित बैठाने में जुट गया है।

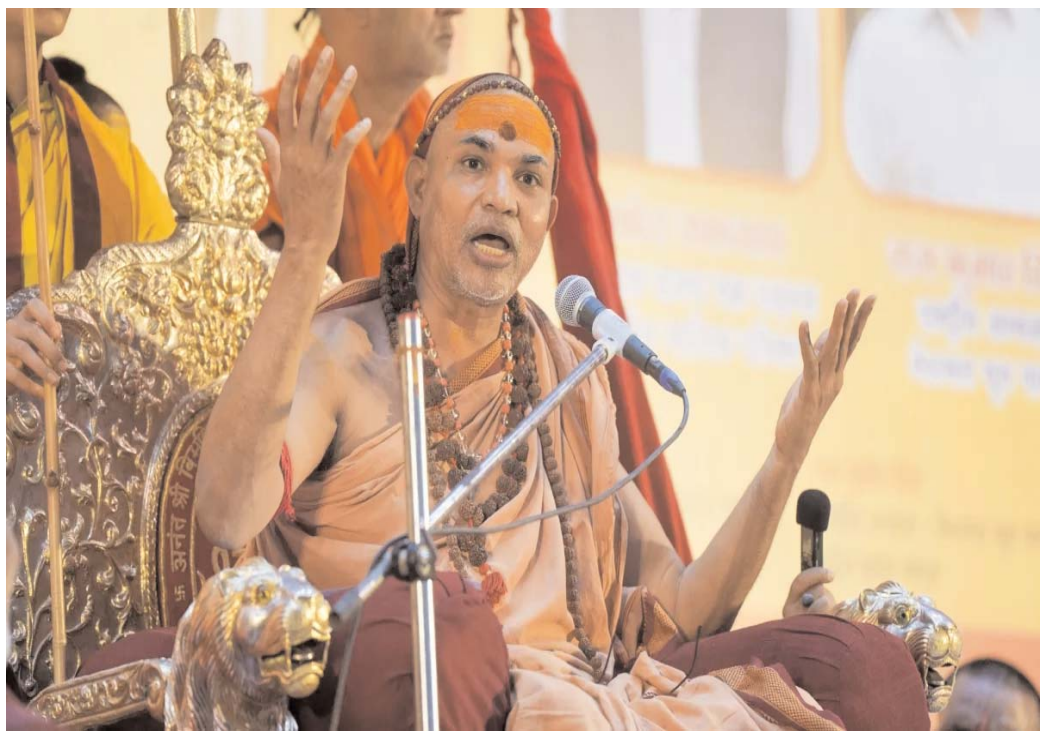

शंकराचार्य ने शिवहर प्रवास के दौरान संवाददाताओं से कहा कि जो गौ माता की रक्षा की बात करेगा वही उनका साथी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति किस धर्म या समुदाय से है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी गौ माता को माँ मानते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं तो वे भी उनके सहयोगी हो सकते हैं। इस बयान ने पूरे राज्य में नई बहस छेड़ दी है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी बड़े धार्मिक नेता ने सीधे तौर पर राजनीति में उतरकर एक ऐसा एजेंडा सामने रखा है जो पूरी तरह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं पर आधारित है।

शिवहर नगर परिषद ने हाल ही में गौ माता को नगर माता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया था। इस निर्णय ने शंकराचार्य की मुहिम को मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने इस पहल को सराहते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश के हर नगर और हर पंचायत इस तरह का निर्णय लें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वयं को गौ मतदाता घोषित करें और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ रक्षा पर स्पष्ट और दृढ़ रुख रखते हों। उनकी यह अपील अब गांव-गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है।

बिहार के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक भावनाएँ हमेशा से गहरी जड़ें रखती हैं। खेती-किसानी करने वाला समाज गाय को केवल धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन-रेखा मानता है। ऐसे में शंकराचार्य की यह मुहिम सीधे किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के दिल तक पहुँच रही है। सीतामढ़ी के परौर गांव के किसान रघुनाथ ठाकुर कहते हैं कि पहले वोट देते समय जाति सबसे बड़ा आधार हुआ करती थी लेकिन अब शंकराचार्य जी ने हमें याद दिलाया है कि गाय हमारी असली पहचान है।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह मुहिम ज़मीनी स्तर पर असर दिखाती है तो कई सीटों पर नतीजे बदल सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों में पहले भी दो से तीन हज़ार वोटों का फर्क निर्णायक रहा है। 2020 के चुनाव में करीब 40 से अधिक सीटें बेहद मामूली अंतर से तय हुई थीं। ऐसे में अगर शंकराचार्य की मुहिम से 2 से 4 प्रतिशत वोट भी इधर-उधर होता है तो भाजपा समेत सभी दलों के लिए यह चुनौती बन सकता है।

भाजपा के लिए यह स्थिति सबसे कठिन कही जा रही है। पार्टी वर्षों से हिंदुत्व और आस्था को लेकर राजनीति करती रही है। लेकिन शंकराचार्य ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में अब तक गौ रक्षा को प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अब भी यह घोषणा कर दे कि वह गाय की रक्षा सुनिश्चित करेगी तो वे उनका समर्थन करेंगे, वरना जनता को यह मान लेना चाहिए कि भाजपा ने वादा निभाने में चूक की है। शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा को नुकसान होगा तो वह उनकी करनी से होगा, न कि शंकराचार्य की तरफसे।

राजद और जदयू के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है। दोनों दल जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं के केंद्र में आने से उनका वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस और वामदलों ने इस मुहिम को चुनावी राजनीति में धर्म को घसीटने की कोशिश बताया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनकी बातों का उतना असर नहीं दिख रहा।

गौ मतदाता संकल्प यात्रा इस समय उत्तर बिहार के दर्जनों गांवों में पहुँच चुकी है। यात्रा में शामिल लोग ढोल-नगाड़ों और भजन-कीर्तन के साथ प्रवेश करते हैं और फिर शंकराचार्य या उनके प्रतिनिधि प्रवचन देते हैं। प्रवचन का केंद्र बिंदु यही रहता है कि गौ माता हमारी संस्कृति की आत्मा हैं और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना हर भारतीय का कर्तव्य है। स्थानीय स्तर पर इस यात्रा का माहौल धार्मिक मेले जैसा हो रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

लेकिन शंकराचार्य की इस मुहिम के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक है। 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना केवल घोषणा करना भर नहीं है, इसके लिए स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क और संसाधनों की ज़रूरत होगी। यह भी सवाल है कि क्या उनके उम्मीदवार जनता तक अपना संदेश पहुँचा पाएंगे और क्या लोग केवल गौ रक्षा के आधार पर अपना वोट तय करेंगे। बिहार के मतदाता आस्था और धर्म से प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन बेरोज़गारी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी नज़रअंदाज़ नहीं करते।

फिर भी यह तथ्य साफहै कि शंकराचार्य ने चुनावी विमर्श को नई दिशा दी है। अब तक बिहार की राजनीति जातीय गठजोड़ और विकास बनाम सामाजिक न्याय के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब गौ रक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। राजनीतिक दलों की चुप्पी बताती है कि वे इस नई लहर का इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जनता इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है।शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण जैसे जिलों में जहां धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं गहरी हैं, वहां शंकराचार्य की अपील का असर सबसे पहले दिख सकता है। इन जिलों में पहले भी देखा गया है कि आस्था से जुड़े मुद्दों पर वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अगर यही स्थिति इस बार भी बनी तो चुनावी नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि शंकराचार्य का यह शंखनाद केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग भी है। यह प्रयोग सफल होगा या सीमित रह जाएगा, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने मुख्यधारा की पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और बिहार की चुनावी राजनीति को नई दिशा दी है। आने वाले महीनों में यह सवाल गूंजता रहेगा कि इस बार बिहार में गाय और गौ माता का मुद्दा कितनी दूर तक जाएगा और क्या यह राज्य की सत्ता का रास्ता बदल देगा।

अकल्पनीय हिंसा, उथल-पुथल गले नहीं उतरता

अवधेश कुमार

नेपाल में उथल-पुथल के बीच सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंतु इसके पूर्व तीन दिनों में नेपाल जिस अकल्पनीय हिंसा, उथल-पुथल और हृदयविदारक घटनाओं से गुजरा उनने सबको डराया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरु द्ध जेन जी के बैनर से जारी विरोध प्रदर्शन कितने उग्र, हिंसक, अराजक और अनेक मायनों में आपराधिक भी हुए। लगता था जैसे उग्र भीड़ नेपाल की राजनीति और सत्ता से संबंधित हर चीज नष्ट करना चाहती हो। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास और उच्चतम न्यायालय जला देना, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, नेताओं को उनके घरों में घुस कर, सड़कों पर दौड़ा कर पीटना और महिलाओं को भी नहीं बख्शना किसी आंदोलन का पर्याय नहीं हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी को जलाया गया। शेर बहादुर देउबा की पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा की पिटाई वाकई हृदयविदारक थी। लगता था जैसे भीड़ किसी भी नेता को नेपाल की धरती पर साक्षात सहन करने को ही तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण ऐसा हिंसक विरोध गले नहीं उतरता।

जरा सोचिए, 28 अगस्त को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और 3 सितम्बर को आंदोलन आरंभ हो गया। ठीक है कि सोशल मीडिया नई पीढ़ी और सक्रिय लोगों के जीवन में इतनी पैठ बना चुका है कि प्रतिबंध सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं हो सकता। नेपाल में सोशल मीडिया के माध्यम से 12 अरब डॉलर माह से ज्यादा का कारोबार हो रहा है। नई पीढ़ी रील बनाने से लेकर अन्य वीडियो आदि से भारी कमाई कर रही है। सोशल मीडिया भुगतान का भी जरिया बन गया है। सरकार का कहना था कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा रहा था, सांप्रदायिक घृणा भी फैलाई जा रही थी।

इसलिए इनका नियमन जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने निबंधन की बात कही थी कि जिसे आधार बना कर सरकार ने प्रतिबंध ही लगा दिया था। उग्र विरोध को देखते हुए प्रतिबंध हटा लिया गया। केवल प्रतिबंध विरोध का कारण होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। यह तो नहीं कह सकते कि नेपाल में असंतोष और विरोध के कारण नहीं थे। 2006 में माओवादियों के शांति समझौते के बाद 2008 में राजशाही के अंत के साथ शुरू संसदीय लोकतंत्र का प्रयोग नेपाल में अनेक विद्रूपताओं का शिकार हुआ। 17 वर्षों में 14 सरकारों के आने-जाने से बड़ा प्रमाण राजनीतिक अस्थिरता का क्या हो सकता है। ओली ने भारत विरोधी चीन के प्रति झुकाव रखने वाले अजीब किस्म के नेपाली राष्ट्रवाद को प्रचलित किया जिनसे उनके समर्थक-विरोधी, दोनों पैदा हुए।

आप देखेंगे कि काफी समय से नेपाल में अलग-अलग किस्म के आंदोलन चलते रहे हैं, जिनमें नेपाल को फिर हिन्दू राष्ट्र घोषित करने तथा राजशाही की पूर्ण वापसी प्रमुख था। इनकी रैलियों में हजारों लोग आने लगे। ओली ने राजा ज्ञानेंद्र की गतिविधियों को रोकने की कोशिश की तथा आंदोलन में तोड़फोड़ के लिए उन पर 7 करोड़ 93 लाख का जुर्माना भी लगाया। उनकी सुरक्षा परिवर्तित कर दी गई। हाल में नेपाल में मुस्लिम तथा ईसाई समुदाय की बढ़ती आबादी के विरुद्ध भी असंतोष बढ़ा है। मुस्लिम आबादी तराई या मधेस क्षेत्र में है, और उसके कारण समाज में असहज स्थिति पैदा हुई है। इसके विरुद्ध भी छोटे-बड़े प्रदर्शन चलते रहे हैं।

नेपाल वि का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र था। 2008 की संविधान सभा सह संसद ने बिना घोषणा के हिन्दू राष्ट्र का अंत कर नेपाल को सेक्युलर देश घोषित किया। इसमें बालेंद्र शाह जैसे रैपर तथा सूदन गुरुंग जैसे एनजीओ संचालकों ने नई पीढ़ी को आकर्षित किया। बालेंद्र ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को पराजित कर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता तथा 2023 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें वि के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल कर दिया। यह नेपाल के लोगों खासकर युवाओं की बदलती प्रवृत्ति का प्रमाण था कि स्थापित नेताओं की जगह ऐसे लोगों को प्रमुखता मिली।

बेरोजगारी के कारण युवाओं का विदेश पलायन नेपाल के लिए आम बात थी। आज नेपाल के लोग दुनिया के अनेक कोनों में हैं, और वहां से प्रभावित हैं। राजनीति, सत्ता, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश संबंध, नेताओं की स्थिति पर गहन विमर्श करते हैं तो वहां असंतोष और विद्रोह के आधार व्यापक थे एवं लोगों में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से उभर कर नई व्यवस्था स्थापित करने का भाव होना स्वाभाविक है। किंतु कई बार हम जल्दबाजी में घटनाओं की पृष्ठभूमि, उसके पीछे की सोच तथा इसके भयावह प्रभावों का आकलन नहीं कर पाते और अराजक विद्रोह को भी न्यायसंगत ठहरा देते हैं। नेपाल अकेला देश नहीं है, जहां राजनीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हो। राजनीति में परिवारवाद या नेताओं के परिवारों का संपन्न और सुख-सुविधाओं से भरे जीवन जीने की स्थिति भी अनेक देशों में है। बेरोजगारी या आर्थिक समस्याओं का सामना अनेक देश कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति इसके पूर्व दक्षिण एशिया में श्रीलंका तथा बांग्लादेश में पैदा हुई। बांग्लादेश की घटना के पीछे अमेरिका और पाकिस्तान की प्रमुख भूमिका थी। शेख हसीना के पलायन के बाद देखा गया कि 1971 के बांग्ला मुक्ति संघर्ष से जुड़े अवशेषों को नष्ट किया गया तथा देश को इस्लामी राज की दिशा में ले जाया गया।

अटल इनोवेशन मिशन और आईएफसीसीआई ने देश भर में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनाने के लिए हाथ मिलाया

पीआईबी

अधिक नवोन्मेषी और समावेशी देश के लिए उद्योग-शिक्षा संबंधों को मजबूत करने हेतु एसओआई पर हस्ताक्षर

पीआईबी । इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईएफसीसीआई) और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर भारत में फ्रांस के राजदूत श्री थिएरी मथौ की उपस्थिति में हुए। उन्होंने सामाजिक विकास के लिए प्रभावशाली भारत-फ्रांस साझेदारी को बढ़ावा देने में आईएफसीसीआई के प्रयासों की सराहना की। यह हस्ताक्षर आईएफसीसीआई सीएसआर कनेक्ट डे 2025 के तीसरे संस्करण के दौरान हुआ, जो नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास में आयोजित किया गया था। इसका विषय था- ÷सतत विकास के लिए स्केल-क्रॉस-सेक्टोरल साझेदारी पर सहयोग÷। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें भारत और फ्रांस के कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां, राजनयिक, सरकारी प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और अन्य सीएसआर हितधारक शामिल थे।

आशय-पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर, आईएफसीसीआई के व्यापक भारत-फ्रांसीसी कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ कार्यनीतिक सहयोग के माध्यम से एसटीईएम शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और नवाचार-संचालित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर (उपलब्धि) है। इस साझेदारी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, पाठ्यक्रम परिदान को बेहतर बनाने और एटीएल कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग-विद्यालयों के बीच गहन जुड़ाव को सक्षम बनाने के लिए सीएसआर और कॉर्पोरेट का सहयोग जुटाना है। आईएफसीसीआई अपनी सदस्य कंपनियों और कार्यान्वयन भागीदारों के साथ मिलकर अपने सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से इस पहल को पूरे देश में आगे बढ़ाएगा। इससे स्कूलों और वंचित समुदायों पर दीर्घकालिक और स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

हस्ताक्षर समारोह भारत में फ्रांस के राजदूत श्री थिएरी मथौ की उपस्थिति में आयोजित किया गया , जिन्होंने सामाजिक विकास के लिए प्रभावशाली भारत-फ्रांस साझेदारी के निर्माण में आईएफसीसीआई के नेतृत्व की सराहना की। श्री मथौ ने कहा, ÷फ्रांस दूतावास में आयोजित आईएफसीसीआई सीएसआर कनेक्ट सेमिनार सामाजिक प्रभाव में भारत-फ्रांस सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। भविष्य में, वर्ष 2026 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इसे भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित करेंगे। यह दृष्टिकोण तकनीक से आगे बढ़कर सामाजिक प्रगति को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के एक प्रमुख आयाम के रूप में अपनाता है। इस संदर्भ में, मैं फ्रांसीसी और भारतीय व्यवसायों को सीएसआर को स्थिरता और सामुदायिक प्रभाव में नेतृत्व प्रदर्शित करने के एक अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।÷ वर्ष 2023 से, आईएफसीसीआई के सीएसआर विभाग ने अपनी सदस्य कंपनियों के लिए 86 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है जो अब तक 15,000 से अधिक हो गई हैं। सीएसआर विभाग देश भर में प्रभावशाली सीएसआर पहलों की योजना बनाने, डिज़ाइन करने और उन्हें क्रियान्वित करने में अपनी सदस्य कंपनियों का सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ये पहल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, आजीविका सृजन और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा सहित विविध विषयगत क्षेत्रों में फैली हुई हैं - ये सभी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

नीति आयोग में एआईएम के मिशन निदेशक दीपक बागला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ÷भारत के सुदूर उत्तरी भाग के एक छोटे से गांव के स्कूल से लेकर सुदूर दक्षिणी छोर तक और पश्चिम से पूर्व तक, देश के हर जिले में नवाचार फल-फूल रहा है। यह केवल संख्या या पैमाने की बात नहीं है, असली कहानी हमारे छात्रों द्वारा तैयार किए जा रहे नवीन समाधानों की गुणवत्ता और विविधता में निहित है। एआईएम ने पहले ही एक करोड़ दस लाख (11 मिलियन) से अधिक छात्र उद्यमियों को प्रभावित किया है और इसे दुनिया के सबसे बड़े जमीनी स्तर के नवाचार कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। आईएफसीसीआई के साथ यह नई साझेदारी पूरे देश में कई और छात्रों तथा युवा उद्यमियों के लिए नवाचार-संचालित शिक्षा का विस्तार करेगी।÷

हस्ताक्षर समारोह में अपने संबोधन में आईएफसीसीआई और एआईएम के प्रतिनिधियों ने कम उम्र से ही नवाचार की संस्कृति को पोषित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। यह सहयोग प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने, और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के बीच क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा। इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईएफसीसीआई) की महानिदेशक सुश्री पायल एस. कंवर ने कहा, ÷यह साझेदारी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। इस साझेदारी के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को पाटना और नवाचार को प्रत्येक छात्र के लिए, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में, सुलभ बनाना है।÷

संयुक्त पहल के तहत एटीएल कार्यान्वयन और संवर्द्धन के लिए चयनित सरकारी स्कूलों की पहचान की जाएगी और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, नवाचार चुनौतियों का आयोजन किया जाएगा, तथा सीखने और विकास के एक स्थायी परितंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह सहयोग भारत के लिए एक समावेशी, नवाचार-आधारित भविष्य के निर्माण के लिए आईएफसीसीआई और एआईएम, नीति आयोग के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।

सरदार वल्लभभाई की विचारधारा और सेवा की भावना को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह

पीआईबी

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे के साथ मिलकर आज सरदार पटेल की चिरस्थायी विरासत को स्मरण करने के लिए 'माई भारत' के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी अभियान, 'सरदारञ्ज150 यूनिटी मार्च' के शुभारंभ की घोषणा की । दो महीने तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना जगाना, भारत को एकजुट करने की सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करना और उन्हें 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के आदर्शों को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रनिर्माण में जनभागीदारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा ÷माई भारत÷ के माध्यम से आयोजित की जा रही ÷विकसित भारत पदयात्राएँ÷ राष्ट्रव्यापी पहल हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना, एकता की भावना को सुदृढ़ करना और स्मृति एवं सहभागी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में नागरिक जुड़ाव को गहरा करना है। सरदारञ्ज150 एकता मार्च भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। यह अभियान राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में आप, विशेष रूप से अमृत पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और भारत के महान नेताओं के शाश्वत योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2025 भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती होगी। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार, देश के लिए सरदार पटेल के अमूल्य योगदान को याद करने के लिए, 2024 से 2026 तक दो वर्षीय समारोह मनाएगी।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि सरदारञ्ज150 एकता मार्च केवल एक स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने और एक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का एक राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने युवाओं से सरदार वल्लभभाई पटेल की विचारधारा और भावना को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरदारञ्ज150 एकता मार्च ÷युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए÷ होगा, जिसकी सभी तैयारियाँ और व्यवस्थाएँ एनएसएस और माई इंडिया के युवा स्वयंसेवकों द्वारा की जाएँगी। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से सरदार पटेल के निस्वार्थ सेवा, एकता और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को अपनाते हुए सभी पहलों में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। 560 से ज़्यादा रियासतों को एकजुट करके एक मज़बूत और अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल की भूमिका से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को इस पदयात्रा के माध्यम से ÷एक भारत, श्रेष्ठ भारत÷ का संदेश फैलाते हुए, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए।

महिला शोधकर्ताओं और विद्वानों को सशक्त बनाना समावेशी ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण का मूल आधार है: श्रीमती सावित्री ठाकुर

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली में भारत शोध यात्रा 2025 को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस भारत शोध यात्रा का आयोजन स्प्रिंगर नेचर ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया। यह यात्रा अनुसंधान में समग्रता, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देने वाली देश की सबसे महत्वाकांक्षी आउटरीच पहलों में से एक है। अपने तीसरे संस्करण में यह यात्रा 15 शहरों और 7 राज्यों के 29 संस्थानों से होकर गुजरेगी। इसमें ओपन एक्सेस, अनुसंधान समग्रता, विविधता, समावेशिता और नैतिक विद्वता पर जोर होगा।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती सावित्री ठाकुर ने ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत शोध यात्रा देश भर के शोधकर्ताओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यह यात्रा शोध में महिलाओं को प्रोत्साहन देती है, विद्वता में नैतिकता को प्रगाढ़ करती है, और अवसरों तथा संसाधनों तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करती है। महिला शोधकर्ताओं और विद्वानों का सशक्तिकरण एक समावेशी ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण का मूल आधार है। नैतिक शोध प्रथाओं को बढ़ावा देकर और ज्ञान तक पहुंच को सर्व-सुलभ करके यह पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष योगदान देती है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में महिला शोधकर्ताओं के लिए सुरक्षित, सहायक और अवसरों से परिपूर्ण वातावरण बनाने पर मंत्रालय का ज़ोर है। उन्होंने स्प्रिंगर नेचर और आईसीएसएसआर की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने इस दौरे में शोध में लैंगिक समानता, नैतिक प्रकाशन प्रथाओं और ÷हर रिसर्च, अवर फ्यूचर÷ पहल पर चर्चाएं शामिल कीं, जो शिक्षा जगत और नीति-निर्माण में महिलाओं की आवाज़ को मुख्यधारा में लाने के मंत्रालय के मिशन के अनुरूप है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष अभियान 5.0 के कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करने को तैयार

भारत में कुष्ठ रोग: रोग-मुक्त भविष्य की ओर

पीआईबी - भारत में कुष्ठ रोग की प्रचलन दर 1981 में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 57.2 थी, जो 2025 में घटकर मात्र 0.57 रह गई है। पाए गए नए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत 2014-15 में रहे 9.04% से घटकर 2024-25 में 4.68% रह गया है। मार्च 2025 तक, 31 राज्य और 638 ज़िलों ने प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 से कम की प्रचलन दर हासिल कर ली है, जिससे भारत राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने में सफल रहा है।

कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग या हैन्सन रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह संक्रमण तंत्रिकाओं, श्वसन तंत्र, त्वचा और आँखों को प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षणों में त्वचा पर रंगहीन धब्बे, स्पर्श, दबाव, दर्द, गर्मी और सर्दी का एहसास न होना, मांसपेशियों में कमज़ोरी, असाध?य घाव, विशेष रूप से हाथों, पैरों और चेहरे में विकृतियां, आँखें बंद न कर पाना और कमज़ोर दृष्टि शामिल हैं। कुष्ठ रोग अनुपचारित रोगियों के साथ निकट और निरन?तर संपर्क के दौरान नाक और मुँह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। इस रोग से डर लगता है क्योंकि यह विकृति का कारण बन सकता है; यही इस रोग से जुड़े पारंपरिक सामाजिक बहिष?कार का कारण भी है। कुष्ठ रोग मल्टीबैसिलरी या पॉसीबैसिलरी हो सकता है। जहाँ एक ओर, मल्टीबैसिलरी कुष्ठ रोग में स्लिट-स्किन स्मिअर परीक्षण में जीवाणुओं का उच्च घनत्व दिखाई देता है, वहीं पॉसीबैसिलरी कुष्ठ रोग के मामलों में स्लिट-स्किन स्मिअर परीक्षण में बहुत कम या कोई जीवाणु नहीं दिखाई देते। भारत में 1983 में बहुऔषधि चिकित्सा (एमडीटी) की शुरुआत ने कुष्ठ रोग के उपचार में क्रांति ला दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा रोगियों को एमडीटी उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। एमडीटी द्वारा शीघ्र निदान और उपचार से विकलांगता और विकृतियों को रोका जा सकता है। एमडीटी की शुरुआत के बाद से, इस रोग की घटनाओं और प्रचलन में उल्लेखनीय कमी आई है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ], 2024)।

स्वतंत्रता के बाद से भारत में इसकी स्थिति

1951 की दशकीय जनगणना के अनुसार यह संख्या 13,74,000 थी और प्रचलन दर 38.1 प्रति 10,000 जनसंख्या थी। भारत सरकार ने कुष्ठ रोग को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान?यता दी और 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974) के दौरान इस कार्यक्रम को केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम बनाए जाने के बाद इसे गति मिली और इसे आवश्यक प्राथमिकता तथा वित्त पोषण भी प्राप्त हुआ। इस समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इस बढ़े हुए कवरेज को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को मजबूत किया गया और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कुष्ठ रोग कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक बन गए। सरकार ने 1983 में शुरू की गई एक योजना के माध्यम से आवंटित क्षेत्रों में एसईटी (सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार) गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया।

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

:: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) ::

//संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना//

निविदा विज्ञप्ति कमांक–पुअराज/एसी–1/निविदा कमांक/253–254/2025 राजनांदगांव, दिनांक–24.09.2025

पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र – अ में निम्नानुसार ठेकेदारों से दो लिफाफा पद्धति, जिसमें एक अमानत राशि व दूसरा निविदा प्रपत्र का लिफाफा होगा, निविदा आमंत्रित किया जाता है :–

निविदा क0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदाकारों की श्रेणी
253	क्षीरपानी पुलिस परिसर डोंगरगढ़ में किचन शेड निर्माण कार्य।	7.27	5500	–तदैव–
254	क्षीरपानी पुलिस परिसर डोंगरगढ़ में डायनिंग हॉल का निर्माण कार्य।	19.59	15000	–तदैव–

निविदा निःशर्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के कार्यालय में रखी हुई सीलबंद पेटी में दिनांक–09.10.2025 के 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं प्राप्त निविदाओं को दिनांक–09.10.2025 के 4.00 बजे उपस्थित निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जाने की प्रकिया प्रारंभ की जावेगी।

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रति निविदा रू. 1000/– की राशि का चालान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के नाम से "लेखा शीर्ष–0055 एम0पी0आर0, उप शीर्ष–800 अन्य रिसिप्ट" के नाम से स्वीकार्य होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक–08.10.2025 तक कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा कार्य की अवधि वर्षा ऋतु सहित दो माह की होगी। निविदाकारों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र (पुलिस विभाग थाना/चौकी/बेस कैम्प या अन्य शासकीय विभाग) में सफलतापूर्वक निर्माण कार्य किये जाने का अनुभव होना अति आवश्यक है। निविदा से सम्बंधित अन्य जानकारी/शर्ते अधोलिखित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक
जिला राजनांदगांव,(छ0ग0)

G-252603953/2

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

राष्ट्रीय पोषण माह 2025: कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को "पोषण संकल्प" की शपथ

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के तहत कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ''पोषण संकल्प'' की शपथ दिलाई। इस दौरान उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने दैनिक जीवन में सही पोषण को अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान ने मोटापे के दुष्परिणाम, मोटापे का समाधान, चीनी और तेल की खपत कम करना,स्थानीयता को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई)/पोषण भी पढ़ाई भी शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। पौष्टिक आहार को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने हेतु जानकारी दी गयी। साथ ही बताया गया कि पोषण आहार युक्त भोजन से दीर्घकाल तक स्वास्थ्य रहने में मदद करता है एवं रोगों से मुक्त करता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने ''वोकल फॉर लोकल'' की अवधारणा पर जोर देते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग की अपील की। आयोजन का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के संदेश को पहुँचाना तथा सामूहिक प्रयासों से एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का निर्माण करना है।

श्री गुरु तेगबहादुर जी की शहीदी यात्रा का हुआ भव्य स्वागत

जांजगीर चांपा / सिख समाज के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वा शहीदी दिवस के अवसर पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा रायपुर से 3 अक्टूबर से निकली शहीदी यात्रा का पामगढ़ पहुचने पर सिख संगत के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मिलकर दुपट्टा चौक से लेकर गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा पामगढ़ तक पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया ।

बताते चले कि यह यात्रा 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से होते हुए रायपुर में समाप्त होगी । शहीदी यात्रा का पामगढ़ पहुचने पर भव्य स्वागत किया गया ,पंज प्यारो की अगुवाई में इस यात्रा का स्वागत किया गया । गुरुद्वारा में पंज प्यारो की अगुवाई में ज्ञानी जी के द्वारा सबद कीर्तन एवं अरदास किया गया।तत्पश्चात सिख समाज द्वारा पंज प्यारो एवं अतिथियों का मोमेंटो एवं सरोपा देकर सम्मानित किया गया । ब्राह्मण संगठन ने गुरुतेग बहादुर जी का तैल चित्र से पंज प्यारो का सम्मान किया।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवको ने पूरे स्वागत रैली की आगवानी की ।इस अवसर पर सिख समाज के महेंद्र सिंह छाबड़ा,इंदरजीत सिंह छाबड़ा, सतपाल सिंह खनूजा, इंदरपाल आजमानी, रंजीत सिंह गांधी,भूपेंद्र सिंह गांधी, सुरजीत सिह गांधी,गुरमीत सिंह गांधी,अशोक जुनेजा, कमल जुनेजा, राजू जुनेजा,राजू गांधी, मिंटू गांधी, चरनजीत गांधी, गोविंद सिंह गाँधी ,रघुवीर सिंह गांधी,राजेन्द्र सिंह गांधी नानक सिंह गांधी,चरनजीत सोढ़ी, मोहन खत्री, श्याम खत्री, राजेश खत्री, गोविन्द खत्री,डॉ डी सी चौधरी, ज्ञानी रोहित सिंह, नरेन्द्र पांडेय, श्यामबिहारी तिवारी,दिनेश थवाईत, अजय दिव्य, कोमल ब्रह्मभट्ट,संजय मिश्रा, सोनाराम यादव,होरीलाल आदित्य, राकेश टंडन,राजन थवाईत, मुकेश कश्यप, सत्यनारायण शर्मा, प्रितपाल सिंह गांधी, गुलजीत सिंह गांधी,सोनू गांधी, रवि गांधी,रिक्की गांधी,लक्की गांधी,शैवी गांधी सहित पामगढ़ अकलतरा की सिख संगत के साथ सर्व समाज,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,ब्राह्मण संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।

संवेदना से संबल तक श्रीमती धर्मीन नायक को अनुकंपा नियुक्ति, शासन की संवेदनशील पहल

जांजगीर चांपा /

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत मिली अनुकम्पा नियुक्ति

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सौपा नियुक्ति पत्र

जांजगीर-चांपा / राज्य शासन द्वारा जारी ÷छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025÷ के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और मानवीयता का परिचय दिया है। नक्सली घटना में अपने पति स्व. श्री जोहन नायक को खो देने वाली ग्राम बोरसी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा निवासी श्रीमती धर्मीन नायक को शासन द्वारा ÷छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025÷ के तहत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार बम्हनीडीह के अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक स्वर्गीय श्री राजेन्द्र भारद्वाज के असमय निधन हो जाने से छत्तीसगढ़ शासन की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत, स्वर्गीय श्री भारद्वाज की पत्नी श्रीमती जानकी बाई भारद्वाज को भी अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। जिला कार्यालय, जांजगीर-चांपा में भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने श्रीमती धर्मीन नायक एवं श्रीमती जानकी बाई भारद्वाज को नियुक्ति पत्र सौंपा।

कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

गांव से लेकर शहर तक लेकर होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जांजगीर- चांपा

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले के विकास कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाले योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने जिले में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के आयोजन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में तीन स्तर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसमें संकुल स्तर पर 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एवं विधानसभा/ विकासखंड स्तर पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एवं जिला स्तर पर नवम्बर में आयोजित होने वाले खेल महोत्सव के आयोजन के लिए सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इस खेल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन देना है।

कलेक्टर ने सभी विकास कार्यों पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि इन कार्यों की प्रगति पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी स्थिति में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। उन्होंने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तथा छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव अभियान से संबंधित सूचनाओं को निर्धारित समय में ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री महोबे ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अब सभी शासकीय कार्यवाही ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही की जाए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस से न केवल कार्य में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी और फाइलों की गति तेज होगी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी नगरीय निकायों में वार्डवार शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि इस योजना से आम नागरिकों को बिजली बिल से राहत और सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को आवेदन हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आगामी 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, इसलिए किसानों को समय जानकारी देकर अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बटांकन, खसरा, जाति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निराकरण करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव, पोषण माह अभियान, मनरेगा, पीएम आवास योजना सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आज जनदर्शन में कुल 48 आवेदन हुए प्राप्त

कलेक्टर ने संवेदनशीलपूर्वक जनसामान्य की सुनी शिकायत एवं समस्याए

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलपूर्वक सुनी। कलेक्टर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज जनदर्शन में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जनदर्शन में आज तहसील बलौदा के ग्राम पंतोरा निवासी श्री गोविंद राम देवांगन मुआवजा राशि दिलाने, ग्राम नवापारा निवासी श्री विकास कुमार पटेल विश्वकर्म योजना का लाभ दिलाने, तहसील जांजगीर के ग्राम मेहंदा निवासी श्री संदीप तिवारी द्वारा बेजा कब्जा हटवाने, ग्राम नवापारा निवासी श्री बलराम कश्यप द्वारा पीएम सम्मान निधि योजना के तहत लाभ दिलाने, तहसील अकलतरा के ग्राम पंचायत बिरकोनी निवासी श्री प्रकाश पाटले व ग्राम पंचायत पीपरसत्ती निवासी श्रीमती द्रोपती बाई प्रोत्साहन राशि दिलाने, श्रीमती भानमती बंजारे प्रधानमंत्री आवास योजना व पेंशन योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने ली पीएम आवास शहरी 2.0 के संबंध में बैठक जिला स्तरीय समिति ने राज्य शासन को भेजा प्रस्ताव

जांजगीर चांपा / प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत जिले में नए मकानों के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करने और उसे राज्य शासन को भेजने के लिए आज कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिले के नगरीय निकायों द्वारा पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत नए मकानों के प्रस्ताव डीपीआर तैयार किए गए थे, जिला स्तरीय समिति द्वारा मकानों के प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को भेजा गया। कलेक्टर ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि शेष पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, इसलिए इस कार्य में तेजी लाना आवश्यक है। बैठक में सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षक हमें शिक्षा और संस्कार दोनों ही प्रदान करते हैं -राजेश्री महन्त

शिवानी स्मृति सेवा संस्थान रायपुर द्वारा आयोजित शिक्षादीप सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए महामंडलेश्वर

संवाददाता

छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज शिवानी स्मृति सेवा संस्थान रायपुर के द्वारा आयोजित शिक्षादीप सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रताप सिंह संस्थापक होली हाट्र्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर ने किया। यह कार्यक्रम मैक कॉलेज ऑडिटोरियम समता कॉलोनी में आयोजित हुआ। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा की देवी माता सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। छात्र-छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित अनेकों शैक्षणिक संस्थानों के प्रबुद्ध शिक्षकों का तथा स्कूली शिक्षा से हटकर सामाजिक क्षेत्र में अन्य विधाओं में लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लगभग 200 शिक्षक स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए गए। लोगों को संबोधित करते हुऐ मुख्य अतिथि राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि- शिक्षकों का समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है वे हमें न केवल शिक्षा अपितु संस्कार भी प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में भले ही कितने ही बड़े से बड़े पद पर क्यों न चला जाए किंतु जब वह अपने शिक्षक से मिलता है तो उसका सम्मान अवश्य ही करता है। शिक्षक भले ही शैक्षणिक कार्यों से अवकाश प्राप्त कर ले किंतु उसके पश्चात भी लोग उन्हें समाज में गुरुजी कह कर के ही बुलाते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि- शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं कर सकता! कारण कि शिक्षक अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित कर देता है। शिक्षकों को समाज को मानवता का पाठ पढ़ाना है, हम तब पढ़ा पाएंगे जब स्वयं मानव बन जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए संदेश में उन्होंने कहा कि -खाना रोटी मां के हाथ का, पीना घर का पानी। पिज़्ज़ा बर्गर कभी ना छूना, बनी रहेगी जिंदगानी।। लोगों को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजीव गुप्ता अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं विजय चोपड़ा सलाहकार छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण अध्यक्ष मुकेश शाह ने तथा आभार सचिव राजेश शाह ने व्यक्त किया एवं विधिवत संचालन डॉक्टर आकांक्षा दुबे ने किया। इसमें शिक्षकों के अतिरिक्त अनेक स्कूलों के प्रिंसिपल, प्रबंधक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

खास खबर

बालको के रामलीला मैदान में विजयादशमी उत्सव धूमधाम से संपन्न

कोरबा-बालकोनगर

विजयादशमी के पावन अवसर पर बालकोनगर के रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम, माता सीता एवं हनुमान जी की भव्य झांकियों और रावण-दहन कार्यक्रम का आयोजन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। पूजा-अर्चना की शुरुआत बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने की। इस अवसर पर सीईओ सहित बालको परिवार के अन्य सदस्यों ने भगवान श्रीराम की आराधना कर कंपनी और क्षेत्र की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि की कामना की। बालकोनगरवासियों ने बालको सार्वजनिक विजयादशमी समिति द्वारा आयोजित इस भव्य उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशाल रामलीला मंचन और रावण दहन का कार्यक्रम धर्म, सत्य और सद्गुणों की शक्ति के असत्य और अन्याय पर विजय का प्रेरणादायी प्रतीक बना। आकर्षक सजावट और नौ दिनों तक आयोजित रामलीला प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में बालकोनगर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु एवं दर्शक पहुंचे। रामलीला मैदान में आयोजित यह सार्वजनिक विजयादशमी बालकोनगर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान बन चुकी है। 44 वर्षों से यह आयोजन अपनी गौरवशाली परंपरा का उत्सव मना रहा है।

नंदकिशोर बुधिया का निधन

कोरबा । प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं सामाजिक हस्ती नंदकिशोर बुधिया का 89 वर्ष की आयु में बिलासपुर में निधन हो गया है। उनके निधन से बुधिया परिवार, व्यापार जगत और उनसे जुड़े लोगों में शोक की लहर छा गई है। नंदकिशोर बुधिया, स्वर्गीय अंतुलाल बुधिया के पुत्र थे, जिन्होंने व्यापारिक घराना अंतुललाल एंड संस÷ और ÷अंतुलाल डिस्ट्रीब्यूटर÷ की नींव रखी। उनके परिवार में भाई सत्यनारायण बुधिया और कांत बुधिया (कोरबा), किशन बुधिया (बिलासपुर), पुत्र विमल बुधिया और संजय बुधिया(कोरबा), तथा पौत्र सिध्दार्थ, आकाश और अपूर्व बुधिया सहित भरा-पूरा परिवार है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

कोरबा,। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी उद्यान, बुधवारी बाजार में स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात नगर पालिका दीपका के समीप स्थित गांधी जी की प्रतिमा एवं शास्त्री जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरज दास मानिकपुरी ने दोनों महान नेताओं के जीवन दर्शन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महात्मा गांधी जहां अहिंसा के पुजारी थे, वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर देश की आत्मा को जागृत किया।

साइकिल थान :-कोरबा में साइकिल थान का हुआ ऐतिहासिक आयोजन

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित 36 प्रतिभागियों ने काफी प्वाइंट की वादियों को किया फतह,

शामिल हुए थे कुल 75 प्रतिभागी

महापौर एवं सीईओ जिला पंचायत ने टी.पी.नगर चैक से साइकिल थान को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया,

साकेत में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं व प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

कोरबा लोकशक्ति।

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की पहल पर कोरबा में पहली बार 53 किलोमीटर लंबे साइकिल थान का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग ने टीपीनगर चैक से साइकिल थान को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। साइकिल थान में आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय स्वयं प्रतिभागी बने, वहीं आयुक्त श्री पाण्डेय सहित कुल 36 प्रतिभागियों ने काफी प्वाइंट की वादियों को फतह किया, जबकि कुल 75 प्रतिभागियों ने '' थान '' में भाग लिया था, साइकिल थान की वापसी पर निगम कार्यालय साकेत में आयोजित कार्यक्रम में महापौर राजपूत ने विजेताओं को पुरस्कृत व सम्मानित किया। **स्वच्छ शहर व स्वच्छ गांव - स्वच्छ तन व मन - निर्मल पर्यावरण** '' की थीम को लेकर '' माउंटेन राइड आन व्हील्स '' की तर्ज पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की विशेष पहल पर कोरबा में साइकिल थान का ऐतिहासिक आयोजन नगर पालिक निगम कोरबा, जिला व पुलिस प्रशासन, खेल विभाग, वन विभाग, साइकिलिंग संघ आदि के सहयोग से किया गया, वहीं आयोजन के सारे इंतजाम निगम द्वारा कराए गए थे। टीपीनगर चैक से बालको होते हुए काफी प्वाइंट तक और फिर उसी मार्ग से वापसी करते हुए नगर निगम कार्यालय साकेत भवन तक कुल 53 किलोमीटर लंबे इस ऐतिहासिक साइकिल थान में आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित कुल 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 36 प्रतिभागियों ने काफी प्वाइंट की वादियों को फतह करते हुए अंतिम छोर तक पहुंचे तथा फिर साकेत भवन तक वापसी की यात्रा भी पूर्ण की। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए आयुक्त श्री पाण्डेय ने भी साइकिल चलाते हुए काफी प्वाइंट के अंतिम छोर तक पहुंचकर पुनः उसी मार्ग से साइकिलिंग करते हुए साकेत भवन तक की यात्रा लगातार बारिश के बीच पूरी की।

दिव्यांशु सिंह रहे प्रथम स्थान पर - साइकिल थान की इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 18 वर्षीय दिव्यांशु सिंह ने 01 घंटे 39 मिनट 25 सेकेण्ड में यह यात्रा पूर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं लक्ष्य रात्रे 01 घंटा 41 मिनट में यह यात्रा पूरी कर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि संतोष गुप्ता ने 01 घंटे 41 मिनट 02 सेकेण्ड में यह यात्रा पूरी की तथा प्रतियोगिता का तीसरा स्थान अर्जित किया, इसी प्रकार महिला प्रतिभागियों में अनम सिद्दीकी प्रथम स्थान पर रही व अनसुईया कंवर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, वहीं टाप टेन के चैथे स्थान पर राम पटेल, पांचवे स्थान पर जुनैद खान, छठवें स्थान पर नैतिक तिवारी, सातवें स्थान पर पुस्कर तिवारी, आठवें स्थान पर देवांशु भानु, नौवें स्थान पर अमितेश सिंह एवं दसवें स्थान पर जाहिद अली रहें।

काफी प्वाइंट की वादियों से 03 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्र - चूंकि पर्यावरण स्वास्थ के साथ-साथ इस आयोजन की प्रमुख थीम '' स्वच्छता व साफसफाई '' भी थी, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी की देखरेख में इस आयोजन के दौरान निगम की स्वच्छता टीम ने काफी प्वाइंट की वादियों व सम्पूर्ण मार्ग के आक्सी जोन से 03 क्विंटल प्लास्टिक कचरा एकत्र किया तथा एक अभियान के रूप सम्पूर्ण मार्ग की साफसफाई की।

विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र - साइकिल थान का समापन नगर निगम कार्यालय साकेत भवन पहुंचकर सम्पन्न हुआ, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके तहत प्रथम पुरस्कार 11 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 07 हजार रूपये तथा तृतीय पुरस्कार 05 हजार रूपये प्रदान किए गए। वहीं महिला वर्ग में प्रथम विजेता को 03 हजार रूपये व द्वितीय विजेता को 02 हजार रूपये की पुरस्कार राशि दिए जाने के साथ ही चैथा व पांचवॉं स्थान प्राप्त करने वाले दो प्रतिभागियों को 02-02 हजार रूपये का पुरस्कार दिया गया। वहीं सबसे ज्यादा कचरा संग्रहण करने वाली टीम को 01 हजार रूपये, दूसरे स्थान पर रही टीम को 700 रूपये तथा तीसरे स्थान पर रही टीम को 500 रूपये दिए गए जबकि चैथी व पांचवीं टीम को 200-200 रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

कोरबा ब्लॉक के ग्राम दोंदरो में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता जागरूकता शिविर का किया आयोजन

कोरबा संवाददाता।

उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार व्यवहार, धोखाधड़ी, शोषण से बचाने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कोरबा ब्लॉक के ग्राम दोंदरो में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान आयोग की अध्यक्षा रंजना दत्ता, सदस्यगण ममता दास एवं पंकज कुमार देवड़ा ने ग्रामीणों को उपभोक्ता अधिकारों से अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रत्येक माह ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सितम्बर माह में कोरबा विकासखण्ड के ग्राम दोंदरो में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता, सदस्यगण सुश्री ममता दास एवं श्री पंकज कुमार देवड़ा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ई-फाइलिंग, ई-हियरिंग सहित उपभोक्ता कानूनों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ता घर बैठे ही ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग के माध्यम से शिकायत दर्ज कर अपना पक्ष रख सकते हैं। शिविर में उपभोक्ताओं को शुल्क अनुचित व्यापार प्रथा सहित बैंक, बीमा, फसल बीमा, बैंक फ्रॉड, फायनेंस आनलाइन खरीददारी सहित अन्य क्षेत्रों के संबंध में उपभोक्ताओं को शासन द्वारा दिए गए अधिकार के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान अधिवक्ता संगीता चैहान एवं आयोग के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर मनीराम श्रीवास द्वारा भी उपभोक्ता कानूनों के संबंध में जानकारी दी।

गांव के सरपंच बंधन सिंह कंवर व अन्य नागरिकों द्वारा भी ग्रामीणों से उपभोक्ता आयोग द्वारा आयोजित शिविर का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर आयोग के कर्मचारीगण संजय शर्मा, राजेश्वर इंग्ले, नूतन राजपूत, गांव के पंच, मितानिन, जनपद सदस्य, कोटवार, वरिष्ठ नागरिक,बालकों थाना में पदस्थ पुलिस कर्मी सहित सैकड़ों महिलाएं व आम नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा उपभोक्ता कानून ई हियरिंग, ई फाइलिंग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

पहले बिगड़ जाता था बजट, अब दूर हो गया है रूपये बचाने का झंझट

पीएम सूर्य घर योजना ने श्रवण अजगल्ले को दी तनाव से मुक्ति

कोरबा संवाददाता।

एनआईटी रायपुर में पढ़े-लिखे श्रवण अजगल्ले एक आर्किटेक्ट है। पाली ब्लॉक के एक वनांचल गांव में इनके पिताजी एक स्कूल में शिक्षक थे। पिताजी की इच्छा थी कि वह अपने कर्मभूमि वाले क्षेत्र में ही निवास करें। पिताजी के इन्हीं इच्छाओं के साथ आर्किटेक्ट श्रवण ने घर का डिजाइन तैयार किया और दो मंजिला घर बनवाया। घर में अलग-अलग कमरे बनवायें। भले ही अब पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद अब भी है। पिताजी के मौत के बाद अपनी माता और अन्य सदस्यों के साथ निवास करने वाले श्रवण अपने घर को हर पल रोशन रखना चाहते हैं, वे घर में ही आर्किटेक्ट से जुड़े कार्य भी कम्प्यूटर से करते हैं। इस दौरान कमरे का लाइट, पंखा और एसी भी चलता है। ऐसा भी नहीं है कि कमरे के पंखे, एसी और लाइट केवल काम के समय ही चलते हैं, काम खत्म होने के बाद भी इन सबका और घर में मौजूद अन्य विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल होता रहता है। एक तरफ विद्युत उपकरणों का उपयोग जारी रहता है तो दूसरी तरफ बिजली का मीटर भी आगे बढ़ते हुए श्रवण के घर बिजली के बिल में बढ़ोत्तरी करता रहता और जब महीने का बिल आता तो उसके घर का बजट भी बिगट जाता था। कई महीनों तक बिजली के उपयोग और बिल में वृद्धि से श्रवण ने हमेशा के लिये झंझट से मुक्ति चाही और आखिरकार उन्होंने घर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से सोलर सिस्टम लगवा लिया।

22 साल देश की सेवा कर घर लौटा जवान, लोगों ने किया भव्य स्वागत

एजेंसी। कोरबा-सक्ती। 22 साल देश सेवा कर वापस लौटे जवान का गांव के लोगों व दोस्तों ने डीजे लेकर रेलवे स्टेशन में स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल था, लोगों ने पटाखे फोड़े और गाजे-बाजे के साथ जवान का स्वागत किया। सक्ति से लगे सिरली गांव के फुलेश्वर सिदार, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर 22 वर्ष तक राष्ट्र रक्षा करने के बाद सेवानिवृत्ति ली, उनका गांव के लोगों ने तथा दोस्तों व परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया। फुलेश्वर सिदार ने देश के कई हिस्सों में सेवा दी, जिनमें अम्बाला, मिशामारी (असम), पूना, सूरतगढ़, दिल्ली और भोपाल शामिल हैं। फुलेश्वर सिदार का स्वागत करने के लिए सिरली गांव सहित आसपास के मित्रजन व ग्रामवासी बड़ी संख्या में उन्हें लेने के लिए बाराद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। भारत माता के जयकारों व पुष्प वर्षा के बीच उनका स्वागत किया गया। बाराद्वार से लेकर सैनिक के सिरली स्थित घर तक जन रैली निकालकर उन्हें गांव लाया गया। सेवानिवृत्त आर्मी फुलेश्वर सिदार का जन्म सक्ती जिले के सिरली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चैनसिंह सिदार और माता का नाम फुलबासन सिदार है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई और हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पोरथा से पूरी की थी।

अब घर में चमक रही सौर रोशनी, बिजली उपभोक्ता से ऊर्जादाता बने सेवकराम

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना और शासन की डबल सब्सिडी से घटा बिजली बिल

कोरिया, संवाददाता

सूर्य की किरणें अब सिर्फरोशनी ही नहीं, बल्कि आमजन की जिंदगी में नई ऊर्जा और आय का साधन भी बन रही हैं।प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना ने बैकुण्ठपुर के निवासी श्री सेवक राम राजवाड़े की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया है। जहां कभी बढ़ते बिजली बिल उनकी चिंता बढ़ाते थे, वहीं अब वे बिजली उपभोक्ता से ऊर्जादाता बन गए हैं।

शून्य बिजली बिल

श्री राजवाड़े ने अपने घर की छत पर 3 केवी का सोलर प्लांट स्थापित कराया है। इस पर 78 हजार की सब्सिडी मिली है। परिणामस्वरूप, पहले जहां हर महीने हजारों रुपये का बिजली बिल चुकाना पड़ता था, वहीं अब उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

आसान प्रक्रिया, बड़ा लाभ

श्री राजवाड़े बताते हैं कि योजना की आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रही। एक बार आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया स्वतः पूरी हो गई और सोलर पैनल समय पर उनके घर पर स्थापित कर दिया गया। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनका कहना है कि इस योजना ने उन्हें न केवल बिजली बिल से मुक्ति दिलाई, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर भी दिया है।

सरकार का प्रयास और लोगों की भागीदारी श्री राजवाड़े ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल सब्सिडी ने इस योजना को आमजन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे लोग जागरूक होकर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना से न केवल घरेलू खपत व बिजली बिल की समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि उपभोक्ता ऊर्जादाता बनकर अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत कर रहे हैं।

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन

संवाददाता

कोरबा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल में रिक्त पदों पर मेरिट सूची के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। इसके लिए 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय एनसीडीसी कोरबा में किया जाएगा। व्याख्याता, शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक, सहायक ग्रेड के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे।

जिला शिक्षा अधिकारी तामेश्वर उपाध्याय द्वारा बताया गया है कि पदवारध् विषयवार दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार 6 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी। 6 अक्टूबर को व्याख्याता भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय 7 अक्टूबर 2025 को शिक्षक विज्ञान, अंग्रेजी,कला, गणित, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल पद हेतु अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक-प्राथमिक शाला, प्रधान पाठक-माध्यमिक शाला का और 9 अक्टूबर को सहायक ग्रेड दो और सहायक ग्रेड 3 का अभिलेख सत्यापन और साक्षात्कार होगा। सभी पदों हेतु अभिलेख सत्यापन का समय सुबह 9:00 बजे से 11:00 तक तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी (मो 8305773677) से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिलेख सत्यापन ध्साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि-समय में परिवर्तन का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय एन. सी. डी. सी. कोरबा में उपस्थित होवे ।हाई स्कूल ध् हायर सेकेण्डरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अन्य व्यवसायिक योग्यता, टी.ई.टी. मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो) की मूल प्रति एवं 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रारूप के साथ लायें। अभ्यर्थी अपना दो नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से साथ लायें। अभ्यर्थी अपने पहचान सत्यापन हेतु किसी भी शासकीय विभाग ध् संस्था द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र ड्राइविंग लाईसेंस आधार कार्ड पेन कार्ड आदि में से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं 02 सेट छायाप्रति स्वप्रमाणिक कर साथ लाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जायेगा तथा निर्धारित तिथि में दस्तावेजो के सत्यापन ध् साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुन कोई भी अवसर प्रदान नही किया जावेगा। यदि आप संबंधित जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जावेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते है अथवा नहीं के निर्धारण करने का अधिकार चयन समिति का होगा एवं इस संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा । केवल अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार की सूची में नाम होने या इस पत्र द्वारा साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहुत किये जाने मात्र के आधार पर अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन एवं नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। उत्कृष्ट विद्यालय हेतु आवेदित पद पर कार्य करने हेतु चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा। यदि समिति किसी विज्ञापित पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त पाती है, तो चयन प्रकिया पुनः किया जायेगा । दस्तावेज सत्यापनध्साक्षात्कार परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है।

कोल इंडिया लिमिटेड के पीएलआई सर्कुलर के आधार पर एसईसीएल के ठेका कर्मियों के लिए बोनस भुगतान की मांग

कोरबा , । ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा जारी किए गए 'परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना' के सर्कुलर को तुरंत लागू करते हुए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के सभी क्षेत्रों में कार्यरत ठेका कर्मियों को दीपावली से पूर्व बोनस का भुगतान करने की मांग की है ।

समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर को इस संबंध में एक ज्ञापन भेजकर मांग किया है कि इस वर्ष भी दीपावली के पूर्व बोनस प्रदान किया जाए और ठेका कामगारो के मांग के अनुरूप अगले वर्ष से दशहरा के पूर्व यह राशि प्रदान किया जाने हेतु उचित कदम उठाये जायें ।

समिति ने अपने ज्ञापन में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के आधिकारिक कार्यालय आदेश संख्या ब्प्स्ध्ब्-5ठध्श्रठब्ध्श्च्ब्ध्म्झ्हतंजपंध्275 दिनांक 26 अक्टूबर 2024 का हवाला दिया है इस सर्कुलर के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से खनन गतिविधियों में लगे ठेका कर्मियों के लिए च्स्प् योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसे वस्तुतः बोनस के रूप में देखा जाता है ।

अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने प्रेस को जारी बयान में कहा, कोल इंडिया ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है कि 8.33 प्रतिशत की दर से यह इंसेंटिव हर वर्ष दीपावली से पहले पात्र ठेका कर्मियों को दिया जाना है यह दर श्पेमेंट ऑफबोनस एक्टश् के तहत न्यूनतम बोनस के बराबर है ।

राज्यपाल ने पीएम जनमन आवास हितग्राही को सौंपी चाबी

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड राजपुर के पहाड़ी कोरवा ग्राम घटगांव में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राही श्री रामकुमार के घर पहुँचकर उन्हें उनके नए आवास की चाबी सौंपी। राज्यपाल ने फीता काटकर नवनिर्मित आवास में गृह प्रवेश कराया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को उनके नए आवास एवं उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने हितग्राही श्री रामकुमार और उनके परिवार से आत्मीयता से बातचीत की। उन्होंने परिवार की आजीविका, बच्चों की पढ़ाई और योजना से हुए बदलावों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान रामकुमार ने बताया कि पहले वे कच्चे घर में डर में रहते थे लेकिन अब योजना अंतर्गत मिले आवास से अपने पक्के घर में सुकून से बेफिक्र होकर सो पाएंगे। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने पहाड़ी कोरवा परिवार से विदा लेते समय उनको उपहार भेंट किया और आगे बेहतर जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रकाश मोदी का हुआ जशपुर आगमन

जशपुर । जिला जशपुर में विगत दिवस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रकाश मोदी का आगमन हुआ। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहभागिता का मूल्यांकन करना तथा जनसमस्याओं को समझते हुए उनके निराकरण के लिए पहल करना था। जशपुर आगमन के उपरांत श्री मोदी ने कलेक्टर रोहित व्यास से सौजन्य मुलाकात की तथा जिला पंचायत के सभाकक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले की सामाजिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की स्थिति जैसे विभिन्न मुद्दों तथा शासन की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की प्रगति किसी भी जिले की समग्र प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने सभी योजनाओं का लाभ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शासन और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हुए आयोग हर संभव प्रयास करेगा कि समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। श्री मोदी द्वारा सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया की आयोग स्तर पर इन मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा जिले स्तर की समस्याओं के संबंध में उपस्थित समाज के लोगों को अपर कलेक्टर के द्वारा समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए आश्वस्त किया गया ।

वैज्ञानिक पद्धति और नवाचारी खनन के माध्यम से विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है छत्तीसगढ़ : सीएम साय

रायपुर। वैज्ञानिक पद्धति और नवाचारी खनन के माध्यम से विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर : वैज्ञानिक पद्धति और नवाचारी खनन के माध्यम से विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री श्री सायछत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल की खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में और सशक्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय, तथा कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित हुए। साथ ही 5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी जारी की गई और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल तथा रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योगों की अपार संभावनाओं को देखते हुए पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है। अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और पाँच नए ब्लॉकों की निविदा आज जारी की गई है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज न्यास नियम-2025 लागू किए गए हैं। डीएमएफ पोर्टल 2.0 से निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया को सशक्त किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है।

उन्होंने कहा कि नई रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है और जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी। सतत खनन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

सामाजिक विकास का मूलमंत्र है शिक्षा, शिक्षा के बिना है जीवन अधूरा : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। सामाजिक विकास का मूलमंत्र है शिक्षा, शिक्षा के बिना है जीवन अधूरा ङ्क मुख्यमंत्री श्री साय

शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सफल जीवन का मार्ग है। सामाजिक विकास का मूलमंत्र शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र – हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रारंभ से ही राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। राज्य गठन के समय जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। इसी तरह हमने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी, ट्रिपल-आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स और सिपेट जैसे संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित किए हैं, जिनका लाभ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को मिल रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नालंदा परिसर के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे युवाओं को दिशा और अवसर दोनों मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समाज को संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज से ही राष्ट्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी समाज के विकास में बाधक है और इस बुराई से दूर रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने समाज से नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की, जो मछुआरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में गंगरेल बांध ठेका प्रथा को समाप्त कर पुनः डुबान क्षेत्रों के किसानों को मत्स्य पालन की अनुमति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मछुआ समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। प्रदेश का पहला एक्वा पार्क हसदेव बांगो जलाशय में लगभग ?37 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। यह एक्वा पार्क मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज़्म– इन चारों क्षेत्रों में नए अवसर सृजित करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में यहाँ 800 केजों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे अनेक पंचायतों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे मछुआ भाइयों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय मछुवारा संघ के सभी पदाधिकारियों और देशभर से पधारे मेहनतकश मछुआ भाइयों-बहनों को राष्ट्रीय सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि निषाद समाज का गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है। हमारे इतिहास और परंपरा के बारे में नई पीढ़ी को बताना और सिखाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव निषाद समाज को अग्रणी स्थान दिया है।

उन्होंने बताया कि जब अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, तब उसी के सामने सरयू नदी के तट पर निषाद राज मंदिर का निर्माण कर समाज को उचित सम्मान दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया है। इस हेतु निषाद समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा।

अलग-अलग क्षेत्र से तीन दोपहिया वाहन पार

रायपुर, 05 अक्टूबर (आरएनएस)। राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने तीन दोपहिया वाहन पार कर दिया। तीनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगल बाजार आजाद चौक निवासी सन्नी सारथी 22 वर्ष ने डीडीनगर थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एमक्यू 9970 को महादेव घाट के विसर्जन घाट में खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में शिवविहार कालोनी डीडीनगर निवासी अभय वर्मा 19 वर्ष ने कोतवाली थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 केजे 3596 को इंडोर स्टेडियम के पार्किंग में खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसी तरहह तीसरे मामले में विवेक वम्र 24 वर्ष अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एचसी 4108 को आरंग के शराब दुकान के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 20 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। तीनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलााफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आदर्श राज्य

रायपुर। खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार को केंद्र में रखकर राज्य ने खनिज प्रशासन में अनेक संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी खनन राज्यों में सम्मिलित हो गया है। राज्य में विश्वस्तरीय लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, टिन अयस्क सहित नवीन अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक तथा रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता प्रमाणित हुई है, जिससे राज्य की वैश्विक पहचान सुदृढ़ हुई है।

छत्तीसगढ़ का खनन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि देश के कुल खनिज उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17 प्रतिशत है। राज्य के खनिज राजस्व में 25 सालों में 34 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के समय जहाँ खनिज राजस्व मात्र 429 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 14,592 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह उपलब्धि राज्य की सुदृढ़ खनिज नीति और सतत प्रशासनिक सुधारों का परिणाम है।

वर्ष 2015 में संशोधित खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित खनिज नीलामी नियम 2015 के तहत अब तक राज्य में 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें 15 लौह अयस्क, 14 बाक्साइट, 18 चूना पत्थर तथा 13 क्रिटिकल व स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉक सम्मिलित हैं। साथ ही, 05 नए ब्लॉकों (02 चूना पत्थर, 01 लौह अयस्क, 01 स्वर्ण और 01 बेस मेटल ब्लॉक) की नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है।संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने खनन अनुसंधान एवं अन्वेषण के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए आईआईटी मुंबई, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद तथा कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू संपादित किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से क्रिटिकल एवं स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की खोज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गति प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के गाइडलाइन-2024 के अनुरूप राज्य में जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2025 अधिसूचित किए गए हैं। राज्य में अब तक 16,119 करोड़ रूपए का अंशदान प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 1,05,653 कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 74,454 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति, निगरानी और प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डीएमएफ पोर्टल 2.0 को क्रियान्वित किया गया है।

शिव मंदिर में आपत्तिजनक कृत्य से फैला तनाव, 9 गिरफ्तार

अशोक नगर सहित आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है

बिलासपुर। शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात शिव मंदिर परिसर में एक युवक द्वारा किए गए आपत्तिजनक कृत्य के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ मुख्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया, बल्कि उपद्रव फैलाने वाले अन्य 8 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे की है जब आरोपी अशरफखान, पिता अनीष खान ने मंदिर परिसर में अनुचित हरकत की। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा और स्थिति तेजी से तनावपूर्ण हो गई।

इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। उन्होंने एक ठेले को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक बाइक सहित अन्य सामान को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित किया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह के नेतृत्व में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपी अशरफ खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 299, 296, और 351(2) के तहत अपराध क्रमांक 1355/25 दर्ज किया गया है। वहीं, उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ भी अलग से मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद इसराईल, अरमान खान, सलमान खान, सहादत्त खान उर्फ छोटू, वैधनाथ यादव, ओमप्रकाश मानिकपुरी उर्फ गब्बर, करण यादव उर्फ केडी, गौकरण साहू उर्फ बोदू और कैलाश साहू के नाम शामिल हैं। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि फरार अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले पर पुलिस की कड़ी नजर है और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। फिलहाल अशोक नगर सहित आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के प्रवास पर पहुंचे

घटगांव में राज्यपाल ने पहाड़ी कोरवा समुदाय से किया संवाद

रायपुर। एक साधारण से पहाड़ी कोरवा ग्राम घटगांव में आज का दिन असाधारण बन गया, जब राज्यपाल श्री रमेन डेका वहां पहुंचे। ग्राम घटगांव में राज्यपाल का आगमन ग्रामीणों के लिए गर्व और उत्साह का अवसर बन गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक परिधान पहनकर कर्मा नृत्य के माध्यम से उनका आत्मीय स्वागत किया।राज्यपाल श्री डेका ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड राजपुर के इस पहाड़ी कोरवा ग्राम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय उत्पादों बांस से बने हस्तशिल्प, वन औषधियाँ और स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार सामग्रियों की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत संचालित आजीविका गतिविधियों, कृषि कार्यों तथा योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड, ऋण पुस्तिका, टीबी मरीजों को पोषण किट तथा महिला स्व-सहायता समूहों को स्वीकृत ऋण के चेक प्रदान किया। राज्यपाल श्री डेका ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र एवं राज्य पीएम जनमन योजना अंतर्गत पहाड़ी कोरवा परिवारों को लाभान्वित कर रहा है। राज्यपाल श्री डेका ने पहाड़ी कोरवा परिवारों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और शासन की योजनाओं के लाभ की जानकारी ली। समूह की स्व-सहायता समूह की दीदियों ने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद वे आजीविका संवर्धन कर आय के स्रोत बढ़ा रही हैं और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने समूह की दीदियों को सुझाव दिया कि अपने साथ और अधिक लोगों को स्व-सहायता समूह में जोड़ें और आजीविका के अवसर बढ़ाएं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की विकास यात्रा में एक उभरते हुए राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य खनिज संपदा से समृद्ध है और यहाँ के लोग मेहनती, सेवा-भावी हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी कोरवा परिवारों की मेहनत और सादगी प्रदेश की पहचान है। उन्होंने बांस उत्पादन और उसके वैल्यू एडिशन को आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बताया तथा पहाड़ी कोरवाओं को बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव बनाए रखने की बात भी कही।

जिले में हाथियों का कहर जारी, चरवाहे की मौत से दहशत

बलरामपुर, 05 अक्टूबर (आरएनएस)। जिले के वाड्रफनगर वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मदनपुर गांव के पास चटनियां जंगल का है, जहां शुक्रवार को हाथियों के हमले में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सोहन सिंह के रूप में हुई है, जो सुबह अपने मवेशियों को चराने जंगल गया था।

दोपहर करीब 12 बजे जंगल में अचानक उसका सामना दो हाथियों से हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, उसके साथ मौजूद एक अन्य ग्रामीण किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। घटना की जानकारी ग्रामीणों को कुछ समय बाद लगी। जब लोग जंगल में सोहन सिंह की तलाश में पहुंचे तो उनका शव बरामद हुआ। तुरंत परिजनों और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वाड्रफनगर के वन परिक्षेत्र अधिकारी रामनारायण राम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए वाड्रफनगर सिविल अस्पताल भिजवाया। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को तात्कालिक राहत के तौर पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों को हाथियों की सक्रियता को लेकर सचेत किया जा रहा है। विभाग की टीम द्वारा गांव-गांव में मुनादी कर हाथियों के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है और लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी रामनारायण राम ने बताया कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना लगातार व्हाट्सएप ग्रुप और फील्ड विजिट के जरिए ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही विभाग की टीम जंगल में गश्त कर रही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और अकेले जंगल की ओर न जाएं, खासकर मवेशियों को चराने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)